



संस्करण : ग्वालियर

वर्ष : 03

अंक : 185

पृष्ठ : 8

मूल्य : 2.00

मंगलवार, 03 फरवरी 2026

ग्वालियर, मुम्बई, लखनऊ एवं प्रयागराज, से एक साथ प्रकाशित एवं गोरखपुर, वाराणसी, आजमगढ़ से प्रसारित

2 पत्रकार वार्ता को सम्बोधित करते हुये माननीय रेल 4 दीवार पर तस्वीरें सजाने का सही तरीका क्या है? 7 मेरी डे वन से एआई..बहन शमिता के बर्थडे

## योगी ने की केंद्रीय बजट की तरीफ,

# प्रधानमंत्री मोदी ने हमेशा नेशन फर्स्ट की भावना को दी प्राथमिकता

लखनऊ। केंद्रीय बजट 2026-27 पर प्रतिनित्रा देते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को कहा कि केंद्र सरकार ने इस बजट में उत्तर प्रदेश के लिए व्यापक और दुर्गामी प्रावधान किए हैं। उन्होंने बजट के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री योगी ने सोमवार को अपने आवास पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए यह बात कही। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में बीते 11 वर्षों में देश ने विकास की जो यात्रा तय की है, उसी का परिणाम है कि आज उत्तर प्रदेश देश की प्रगति में निर्यात योगदान दे रहा है। भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर तेजी से बढ़ रहा है, जो सुदृढ़ नीतियों और सुशासन का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने हमेशा नेशन फर्स्ट की भावना को प्राथमिकता दी है। अधिकारों के साथ-साथ नागरिक कर्तव्यों की बात करना भी उतना ही

आवश्यक है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मौलिक अधिकारों की चर्चा तो होती है, लेकिन कर्तव्यों की उम्हणा कर दी जाती है, जबकि हर भारतीय को अपने



कर्तव्यों का बोध कराना जरूरी है। वर्तमान बजट इसी सोच को मजबूती देता है। योगी ने कहा कि यह बजट समावेशी विकास को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। किसान, युवा, महिलाएं और परीसरक न के बड़े बजट का प्रावधान किया है। इसके अलावा भारत को डाय सेंटर हब बनाने के लिए 22

10 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जिससे उत्तर प्रदेश के छोटे और मध्यम उद्योगों को बड़ा लाभ मिलेगा और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। उन्होंने कहा कि यह बजट भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाया गया है और उत्तर प्रदेश इससे सर्वाधिक लाभ उठाने वाला राज्य होगा। बजट में प्रस्तावित सात रेलवे कॉरिडोर में से दो कॉरिडोर उत्तर प्रदेश को मिले हैं। आने वाले समय में इससे राज्य को बेहतर कनेक्टिविटी, तेज रेल सेवाओं और आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि का लाभ मिलेगा। साथ ही, अंतर्देशीय जलमार्गों (वाटरवेज) के उपयोग से भी प्रदेश को फायदा होगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि ललितपुर में 1200 एकड़ भूमि पर बायोफार्मा सेक्टर को विकसित किया जा रहा है। ग्लोबल बायोफार्मा के लिए केंद्र सरकार ने बड़े बजट का प्रावधान किया है। इसके अलावा भारत को डाय सेंटर हब बनाने के लिए 22

हजार करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जिसका सीधा लाभ उत्तर प्रदेश को मिलेगा। उन्होंने कहा कि देश में सबसे अधिक ग्राम पंचायतें उत्तर प्रदेश में हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। इससे युवाओं को आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनाने में मदद मिलेगी। महिलाओं के सशक्तिकरण पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं को विभिन्न सेक्टरों में काम करने के अवसर मिल रहे हैं। केंद्र सरकार की योजना के तहत हर जनपद में कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री का आभार जताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश तेजी से पर्यटन हब के रूप में उभर रहा है। माघ मेले में उपलब्ध कराई गई सुविधाओं से यह स्पष्ट है कि थोड़े से प्रयास और बेहतर व्यवस्थाओं से हर धार्मिक और सांस्कृतिक स्थल को बड़े पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जा सकता है।



**नई दिल्ली :** पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दिल्ली में चुनाव आयोग कार्यालय से बाहर आते ही एसआईआर मुद्दे पर तीखा आलोचना की। उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया में व्यापक मिसमैपिंग और असंगतियां सामने आई हैं, जिससे मतदाता सूची में बड़ी गड़बड़ी हुई है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दिल्ली के चुनाव आयोग कार्यालय से बाहर आते ही विवादित

बयान दिया। उन्होंने कहा कि वह इस पूरे मामले से बहुत दुखी हैं। ममता ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग ने बंगाल को विशेष रूप से निशाना बनाया है और 58 लाख लोगों के नाम मतदाता सूची से हटाए उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग ने सही योजना के बिना राज्यों में एसआईआर प्रक्रिया लागू की, जबकि चुनावी राज्यों को छोड़ देना चाहिए था। ममता ने कहा अगर एसआईआर करनी थी, तो पहले चुनाव से बंधे राज्यों को छोड़कर सही योजना के साथ करनी चाहिए थी। लेकिन ऐसा नहीं किया गया। असम में भाजपा की सरकार है, वहां एसआईआर नहीं की गई, लेकिन पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में इसे लागू किया गया। इसका परिणाम हमारे लिए बहुत भारी पड़ा। उन्होंने आगे कहा 58 लाख लोगों के नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए हैं। बहुत सारी गड़बड़ियां और मिसमैपिंग हुई है।

यह भी सवाल किया कि बंगाल को क्यों निशाना बनाया जा रहा है। 58 लाख लोगों के नाम मतदाता सूची से हटाए उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग ने सही योजना के बिना राज्यों में एसआईआर प्रक्रिया लागू की, जबकि चुनावी राज्यों को छोड़ देना चाहिए था। ममता ने कहा अगर एसआईआर करनी थी, तो पहले चुनाव से बंधे राज्यों को छोड़कर सही योजना के साथ करनी चाहिए थी। लेकिन ऐसा नहीं किया गया। असम में भाजपा की सरकार है, वहां एसआईआर नहीं की गई, लेकिन पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में इसे लागू किया गया। इसका परिणाम हमारे लिए बहुत भारी पड़ा। उन्होंने आगे कहा 58 लाख लोगों के नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए हैं। बहुत सारी गड़बड़ियां और मिसमैपिंग हुई है।

## SIR पर चुनाव आयोग से मिलीं ममता:

# बंगाल को बनाया जा रहा निशाना, आयुक्त को बताया अहंकारी और झूठ

## राजधानी में कोहरे के साथ प्रदूषण की दस्तक, दिल्ली की हवा फिर बिगड़ी



**नई दिल्ली।** राष्ट्रीय राजधानी में सोमवार सुबह घना कोहरा छाया रहा और औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) मध्यम श्रेणी में दर्ज किया गया। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के अनुसार, तड़के पालम और सफ़दरजंग दोनों स्थानों पर हृश्यता घटक 100 मीटर रह गई। दिल्ली में एक्यूआई 188 रहा जबकि 21 केंद्रों पर वायु गुणवत्ता प्रथम्यमश श्रेणी में थी और 16 केंद्रों पर यह खराब श्रेणी में दर्ज की गई। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के समीर ऐप के अनुसार, तीन निगरानी केंद्रों का एक्यूआई डेटा तत्काल उपलब्ध नहीं था जबकि लोथो

रोड केंद्र में एक्यूआई 116 दर्ज किया गया, जो सभी केंद्रों में सबसे कम था। सीपीसीबी के अनुसार, शून्य से 50 के बीच एक्यूआई को अच्छा, 51 से 100 को संतोषजनक, 101 से 200 को मध्यम, 201 से 300 को खराब, 301 से 400 को बहुत खराब और 401 से 500 के बीच एक्यूआई को गंभीर श्रेणी में माना जाता है। वायु गुणवत्ता पूर्व चेतावनी प्रणाली (एन्यूईडब्ल्यूएस) के अनुसार, दिल्ली की वायु श्रेणी वना अगले दो दिनों तक खराब श्रेणी में रह सकती है जबकि अगले छह दिनों के लिए भी वायु गुणवत्ता के खराब श्रेणी में रहने का अनुमान है।

आईएमडी ने बताया कि सफ़दरजंग में न्यूनतम तापमान 10.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से थोड़ा अधिक है जबकि पालम में न्यूनतम तापमान सामान्य से थोड़ा अधिक 10.7 डिग्री सेल्सियस रहा।

## संसद में धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस

# प्रधानमंत्री मोदी 4 फरवरी को देंगे जवाब



**नई दिल्ली।** संसदीय मामलों के केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने सोमवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 फरवरी को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देंगे। सोमवार को शुरू हो रही मसौदा बहस को डिटेल्स शेयर करते हुए,

उन्होंने कहा कि सबानंद सोनोवाल चर्चा शुरू करेंगे और इसमें आज भाजपा के पांच जाने-माने स्पीकर शामिल होंगे। उन्होंने लगातार नेगेटिव सोच रखने और यूनियन बजट के पॉजिटिव पहलुओं को मानने से इनकार करने के लिए विपक्ष की

आलोचना भी की। रिजिजू ने कहा कि आज हमारे पास भाजपा के पांच स्पीकर हैं क्योंकि कुल चर्चा का समय 18 घंटे है जो तीन दिनों में फैला हुआ है। इसे ध्यान में रखते हुए, एनडीए को लगभग 55 प्रतिशत समय मिलेगा। प्रस्ताव सबानंद सोनोवाल पेश करेंगे और तेजस्वी सूया उसका समर्थन करेंगे। उसके बाद, विपक्ष के नेता बोलेंगे। वहाँ, प्रधानमंत्री मोदी 4 फरवरी को शाम को जवाब देंगे। उन्होंने आगे कहा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के बाद यूनियन बजट पर विस्तार से बहस होगी। आज राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव हैय इस पर चर्चा तीन दिनों के लिए 18 घंटे तक होनी है। उसके बाद, बजट पर चर्चा होगी।

विपक्ष पर तीखा हमला करते हुए रिजिजू ने उस पर जानबूझकर बजट में बताई गई उपलब्धियों को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि विपक्ष बजट के पॉजिटिव पहलुओं को मानने को तैयार नहीं है। मैं इसे ठीक नहीं कर सकता। आज पूरी दुनिया भारत का बजट देख रही है। यह अब सिर्फ भारतीयों के लिए नहीं है, दुनिया भर के लोग भी भारत का बजट देखते हैं। मौजूदा सरकार के आर्थिक नजरिए की तुलना पिछली यूपीए सरकार से करते हुए रिजिजू ने कहा कि कैपिटल खर्च में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने कहा कि अगर आप इसकी तुलना यूपीए सरकार के समय से करें, तो कैपिटल खर्च में बहुत बड़ी बढ़ोतरी हुई है। अब यह लगभग

12.5 लाख करोड़ रूप है। उन्होंने कांग्रेस पर बजट को लेकर नेगेटिव सोच के साथ लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया। रिजिजू ने कहा कि बजट के बारे में कांग्रेस की सोच इतनी नेगेटिव है कि वे लोगों को गुमराह कर रहे हैं। दुनिया जानती है कि भारत आर्थिक रूप से तेजी से तरक्की कर रहा है। यह ऐसी बात नहीं है जिसके बारे में झूठ बोला जाए। भारत की बढ़ती ग्लोबल आर्थिक हैसियत पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना चाहती है। पहले हम मोबाइल फोन एक्सपोर्ट नहीं करते थे, लेकिन अब हम दूसरे लेवल पर तरक्की कर रहे हैं। ये वो बातें हैं जिन्हें विपक्ष देखने से मना कर रहा है।

## दिल्ली हाईकोर्ट ने रद्द किया जामिया के पूर्व कुलपति इकबाल हुसैन का निलंबन

**नई दिल्ली।** दिल्ली उच्च न्यायालय ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया (जेएमआई) के पूर्व कुलपति प्रोफेसर इकबाल हुसैन के निलंबन को निरस्त करते हुए कहा है कि उनके खिलाफ चलायी गयी अनुशासनात्मक कार्यवाही न तो उनके पक्ष में थी और न ही संस्थान के पक्ष में। मुख्य न्यायाधीश देवेन्द्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस करिया की खंड पीठ ने प्रोफेसर हुसैन को एक याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया, जिसमें उनके निलंबन को चुनौती दी गयी थी। जेएमआई विश्वविद्यालय ने सुनवाई

के दौरान न्यायालय को बताया कि उसने छह सितंबर 2024 के निलंबन आदेश को पहले ही वापस ले लिया है और इसके लिए 20 जनवरी 2026 को एक नया आदेश जारी किया गया था। न्यायालय ने इसी बात को रिपोर्ट पर लेते हुए प्रोफेसर हुसैन को उनकी अकादमिक और शैक्षिक जिम्मेदारियां फिर से शुरू करने की इजाजत दे दी। साथ ही न्यायालय ने यह निर्देश दिया कि जब तक अनुशासनात्मक कार्यवाही पूरी नहीं हो जाती, तब तक वे एस्टेट ऑफिसर के तौर पर काम नहीं करेंगे। न्यायालय ने कहा कि विभागीय जांच डेढ़ साल से ज्यादा समय से लंबित थी

और माना कि इतनी लंबी जांच से बेवजह परेशानी होती है। इसलिए, पीठ ने विश्वविद्यालय को छह हफ्ते के अंदर जांच पूरी करने का निर्देश दिया। यह मामला जेएमआई की कार्यकारी परिषद के एक फैसले से जुड़ा है, जिसमें विधि संकाय के पूर्व डीन और सेवा न्यायशास्त्र के जाने-माने विशेषज्ञ प्रोफेसर हुसैन से विश्वविद्यालय के जमीन खरीदने के पहले अधिकार के बारे में सय देने को कहा गया था। प्रोफेसर हुसैन ने जमीन खरीदने के खिलाफ सलाह देते हुए सुझाव दिया कि विश्वविद्यालय को अपनी मौजूदा जमीन का सही इस्तेमाल करना चाहिए।

## सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र व यूपी समेत 12 राज्यों के धर्मांतरण विरोधी कानूनों पर जारी किया नोटिस, 4 हफ्ते में मांगा जवाब



**नईदिल्ली।** उच्चतम न्यायालय ने धर्मांतरण रोधी कानूनों की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली नेशनल कार्ड्सिल ऑफ चर्चेंज इन इंडिया (एनसीसीआई) की नयी याचिका पर सोमवार को केंद्र के साथ-साथ राजस्थान और अरुणाचल प्रदेश सहित 12 राज्यों को नोटिस जारी किया। एससीसीआई द्वारा

वरिष्ठ अधिवक्ता मीनाक्षी अरोड़ा के जरिये दाखिल इस जनहित याचिका में धर्मांतरण रोधी कानूनों के क्रियावन्धन पर तत्काल रोक लगाने का अनुरोध किया गया है। प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने एनसीसीआई की दलीलों पर संज्ञान लेते हुए केंद्र तथा 12 राज्य सरकारों से चार सप्ताह के भीतर जवाब तलब किया। प्रधान न्यायाधीश ने नयी जनहित याचिका को इसी मामले में दाखिल अन्य याचिकाओं के साथ संबद्ध करने का निर्देश देते हुए कहा कि तीन न्यायाधीशों की पीठ इन सभी पर एक साथ सुनवाई करेगी। केंद्र सरकार

का पक्ष रखने के लिए पीठ के समक्ष उपस्थित हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि राज्य के कानूनों को चुनौती देने वाली इसी तरह की याचिकाएं लंबित हैं। उन्होंने कहा, हमारा जवाब तैयार है और जल्द ही दाखिल किया जाएगा। अरोड़ा ने दलील दी कि ओडिशा और राजस्थान ने भी अपने अलग-अलग कानून बनाए हैं जिन्हें पूर्व में दाखिल याचिकाओं में चुनौती नहीं दी गई है। उन्होंने कहा, अन्य अधिनियमों में भी संशोधन किया गया है जिन्हें चुनौती नहीं दी गई है। मैं सभी स्थायी अधिवक्ताओं को नोटिस देना चाहती हूँ। पीठ ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद कहा,

नोटिस जारी करें। प्रत्येक नोटिस की एक प्रति राज्यों के महाधिवक्ताओं को भी भेजी जाए। केंद्र और 12 राज्यों की ओर से चार सप्ताह के भीतर जवाबी हलफनामा दाखिल किया जाए। प्रतिवादी एक संयुक्त जवाबी हलफनामा दाखिल करें। मामले के महत्व के मद्देनजर इसे तीन न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। ईसाई निकाय का पक्ष रखने के लिए पेश हुई अरोड़ा ने दलील दी कि कुछ राज्य कानून ऐसे हैं जो तथाकथित धर्मांतरण के खिलाफ सतर्कता समूहों को शिकायत करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, और इसलिए कई शिकायतें दर्ज की जा रही हैं।

## मनरेगा परिवर्तनकारी कानून था, जी राम जी अधिनियम खामियों से भरा है: कांग्रेस



**नईदिल्ली।** कांग्रेस ने सोमवार को दावा किया कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) एक परिवर्तनकारी कानून था, जबकि मोदी सरकार द्वारा लाया गया विकसित भारत-जी राम जी अधिनियम खामियों से भरा हुआ है। पार्टी महासचिव जयमन शंभर ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पुष्पनी तस्वीर साझा कर दोनों कानूनों की तुलना की। वह तस्वीर आंध्र प्रदेश की एक महिला लाभार्थी को सबसे पहले मनरेगा जांब कर्ड प्रदान किए जाने से संबंधित है। शंभर ने एक्स पर पोस्ट

किया, आज से ठीक 20 साल पहले, मनरेगा को आंध्र प्रदेश के अन्तर्पुर जिले के बदनापल्ली गांव में शुरू किया गया था। इन 20 वर्षों के दौरान, मनरेगा ने ग्रामीण परिवारों (विशेष रूप से महिलाओं) को 180 करोड़ कार्य-दिवस प्रदान किए, अनुमानित 10 करोड़ सामुदायिक परिस्मृतिपाया तैयार कीं, पलायन को काफी हद तक कम किया, ग्राम पंचायतों को सशक्त बनाया और ग्रामीण गरीबों की ज्यादा मजदूरी के लिए मोलभाव करने की शक्ति को निर्णायक रूप से बढ़ाया है। उनका कहना है कि मनरेगा ने इसकी मजदूरी को सीधे बैंक और ड्रकषर खातों में जमा करने के लिए प्रत्यक्ष अंतरण पहल की भी शुरूआत की। पूर्व ग्रामीण विकास मंत्री ने कहा, मनरेगा एक मांग-आधारित कानूनी गारंटी अधिनियम था, सिर्फ एक प्रशासनिक वादा नहीं था।

## राहुल गांधी ने लोकसभा में किया पूर्व सेना प्रमुख नरवणे की किताब का जिक्र, भड़के राजनाथ-अमित शाह, कार्यवाही बाधित



**नई दिल्ली।** लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सोमवार को सदन में एक पूर्व सेना प्रमुख के संस्मरण के मौसोंदे के कुछ अंश पढ़ने का प्रयास किया, जिस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह ने विरोध जताया और फिर

स्थगित कर दी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कांग्रेस नेता से कई बार यह अपील की कि वह पुस्तक या किसी पत्रिका को सदन में उद्घृत नहीं कर सकते, हालांकि राहुल गांधी ने पूर्व सेना प्रमुख का हवाला देते हुए चीन के साथ भारत के सैन्य तनाव का विषय उठाने का प्रयास किया और दावा किया कि पूर्व सेना प्रमुख ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के चरित्र के बारे में भी बताया है। राजनाथ सिंह ने राहुल गांधी पर सदन को गुमराह करने का प्रयास करने का आरोप लगाया। लोकसभा में गतिरोध के समय प्रधानमंत्री मोदी भी मौजूद थे। राहुल गांधी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लाए गए धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में भाग लेते हुए अपने भाषण

की शुरूआत में ही भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या के वक्तव्य का उल्लेख करते हुए पलटवार करने का प्रयास किया। उनका कहना था कि सूर्या ने कांग्रेस की देशभक्ति और चरित्र पर सवाल खड़े किए हैं, इसलिए वह एक पूर्व सेना प्रमुख के उस संस्मरण के अंश को पढ़ना चाहते हैं जो एक पत्रिका में प्रकाशित हुआ है। उन्होंने जैसे ही इसे पढ़ने का प्रयास किया तो राजनाथ सिंह ने सवाल उठाया कि नेता प्रतिपक्ष को बताना चाहिए कि वह जिस पुस्तक को उल्लेख कर रहे हैं, वो प्रकाशित हुई है या नहीं। गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा कि सदन में पुस्तक और पत्रिका में प्रकाशित बातों को नहीं रखा जा सकता और नेता प्रतिपक्ष को

व्यवस्था का पालन करना चाहिए। बिरला ने राहुल गांधी से कई बार कहा कि वह राष्ट्रपति के अभिभाषण पर अपनी बात रखें। जब राहुल गांधी इस संस्मरण के कुछ अंश सदन के पटल पर रखने पर अड़े रहे तो बिरला ने कहा, आप लगातार आसन की अवमानना कर रहे हैं...। राहुल गांधी ने कहा कि वह आसन को चुनौती नहीं दे रहे हैं, बल्कि चीन के साथ भारत के रिश्ते के बारे में बात खरना चाहते हैं। सदन में लगातार गतिरोध बने रहने पर बिरला ने लोकसभा की बैठक अपराह्न दो बजकर नौ मिनट पर अराह्न तीन बजे तक के लिए स्थगित कर दी।





## संपादकीय

### बजट-2026: रोना हँसना दोनों मना कार्टून

बजट को लेकर वैसे भी आम आदमी की सोच केवल महंगाई और बेरोजगारी रोकने तक टिकी रहती है। जबकि पक्ष और विपक्ष हमेशा की तरह बजट अपना राग अलापता नजर आया। सरकारी नौकरी पेशा, व्यापारी, उद्योगपति और अन्य संघर्ष हमेशा बजट को लेकर अपने हानि लाभ के हिसाब से चर्चा, प्रतिक्रिया देते रहे है। यही बाँट 2026 के केन्द्रीय आम बजट को लेकर सामने आ रही है। विपक्ष और सरकारी सेवकों के नेतृत्व ने जहाँ आम बजट 2026 को एक सिरि से अलाभकारी, आतूदशी बताया है वहीं सत्ता पक्ष से जुड़े नेताओं, केन्द्रीय मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों ने जहाँ जमकर आम बजट की सरगना करते हुए इसे दूरगामी लाभकारी बताया है। बहरहाल आम जनता जो दो जून के लिए रोजी रोटी के लिए संघर्ष कर रही है उसके लिए बजट ना रोना जैसा है औ न ही हँसने जैसा है। बजट में रोने पर भारी टैक्स लादकर बड़ा प्रहार किया गया है। लेकिन इसका फायदा एक बार फिर इस व्यापार को चलाने वाले दिग्गजों के खाते में दर्ज होगा। वैसे सरल शब्दों में कहे तो बजट एक ऐसा प्रयास है जो पारंपरिक रूप से ज्यादा भटकता नहीं है, बुनियादी बातों पर कायम रहता है और राजकोषीय सुदृढ़ीकरण के लक्ष्यों के प्रति विवेकपूर्ण दृष्टिकोण बनाए रखता है। बहरहाल इसे एक निराशाजनक प्रयास कहा जा सकता है। बाजारों से फुलें तो वे इसे भी बुरा कहेगी, खासकर शेयरों में आई भारी गिरावट को देखते हुए, जो केंद्रीय बजट पेश होने के बाद पिछले छह वर्षों में देखी गई सबसे बड़ी गिरावट थी। महंगाई और बेरोजगारी को लेकर केन्द्रीय बजट में सरकार की कोई स्पष्ट संशा सामने नहीं आई है। अगर बजट की बारीकियाँ आम जनता को समझान में सतारूढ़ पार्टी समझाने में असफल रही तो इसका फायदा आमगी चुनावों में विपक्ष को मिले ऐसी सम्भावनाओं को नकरा नहीं जा सकता। वैसे तो इस बजट से अलग-अलग सेक्टर से जुड़े देश के नागरिकों की ढेरों उम्मीदें जुड़ी हुई थीं। खासतौर से टैक्स पेयर्स को टैक्स स्लैब में कुछ नए बदलाव और कुछ नई छूट की आशा निराशा में तब्दील कर दी गई। हालांकि कुछ सेक्टरस में कुछ बड़ी रिबावत दिए जाने की घोषणा की गई है। बजट में बड़े और दीर्घकालिक सुधार पर सरकार गति को बनाए रखने के संकेत दिये गए है। हर बार की तरह शराब, सिगरेट व तंबाकू प्रेमियों की जेब ढीली होगी। नये प्रावधानों में विदेशों में पढ़ रहे छात्रों को भेजे जाने वाले पैसे पर टीसीएस कम होगा। माइक्रोवैच, सोलर पैनल, चमड़ा उत्पाद, 17 दवाइयां तथा सात दुर्लभ बीमारियों की दवाएं सस्ती होगी हालांकि, एसटीडी बढ़ने के मुद्दे पर शेयर बाजार को बजट रास नहीं आया विदेशी यात्रा फैंकेज पर भी छूट दी गई है। आने वाले महीनों में जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव होंगे, उनका भी बजट में खास ख्याल रखा गया है। दुनिया में इलेक्ट्रॉनिक व अन्य उत्पादों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते दुर्लभ खनिज रेश पर ध्यान केंद्रित कर रेशर अर्थ कॉरिडोर बनाने का लक्ष्य रखा गया, जिसमें तमिलनाडु-केरल का खास ध्यान रखा गया। आसन्न चुनाव वाले इन राज्यों के मछुआरों व नारियल उत्पादकों को प्रोत्साहन व छूट दी गई है। इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए इस उद्योग में चालीस हजार करोड़ रुपये के निवेश का प्रस्ताव है। वहीं सस्ती दवाओं के लिए बायोफार्मा शक्ति योजना के लिए दस हजार करोड़ रुपये का प्रावधान होगा, जिससे देश में मधुमेह व कैंसर की सस्ती दवाइयाँ उपलब्ध हो सकेंगी। दूसरी ओर आसन्न चुनाव वाले राज्यों पश्चिम बंगाल, असम व तमिलनाडु को हाई-स्पीड ट्रेन कॉरिडोर का लाभ देने का प्रस्ताव है। वहीं असम को बौद्ध सर्किट का लाभ दिया गया है। यह योजना बौद्ध तीर्थों के विकास, यात्री सुविधाओं के विस्तार तथा यहां तक कि तीर्थयात्रियों की पहुंच आसान बनाने की कोशिश है। वहीं दूसरी ओर डिजिटल मनोरंजन व्रतित हेतु रचनात्मक बढ़ाने वाली ऑरेंज इकॉनमी को भी प्राथमिकता बनाया गया है ताकि इस क्षेत्र में युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों में वृद्धि की जा सके। अप्रैल 26 तक नया आवक कम्पू लागू करने की बात बजट में कही गई है, जिसमें अक्वोर रिटर्न की पछड़ियों से जुड़ी समय सीमा और नियमों में बदलाव होगा। निश्चित रूप से दुनिया आपूर्ति श्रृंखला में जारी वैश्विक उथल-पुथल और टैरिफ युद्ध के बीच राजग सरकार ने आम बजट में आत्मनिर्भरता को प्राथमिकता दी है। साथ ही आजादी के सौ साल पूरे होने पर भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प की दिशा में भी कदम बढ़ाया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने बजट की दशा-दिशा पर तीन शब्दों में संदेश दिया कि यह स्क्रिल, स्केल और सरस्टेनबिलिटी का बजट है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि यह विकास व आत्मनिर्भरता के लिए बजट है। बजट पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने युवाओं, किसानों, निवेशकों का जिन्न करते हुए दावा किया कि ये बजट भारत के असली संकटों से अनजान है। राहुल गांधी ने कहा है कि केंद्रीय बजट में भारत के सामने मौजूद वास्तविक संकटों से आंख मूंद ली गई। विपक्षी नेताओं ने आरोप लगाया कि इसमें आम आदमी के लिए कुछ खास नहीं है। यही नहीं इस बजट से मिडिल क्लास को खासी उम्मीदें थीं. आवकर में छूट और महंगाई पर काबू जैसे प्लान के इंतजार कर रहे थे। सांघिर सिटीजन को भी रेल किराये में छूट संभेत की उम्मीदें थीं। लेकिन वित्त मंत्री आम आदमी से जुड़े मुद्दों से किनारा करते हुए सरकार के मिशन 2047 पर तथस्थ दिखाई पड़ी। कुल मिलाकर यह बजट मीडिल क्लास, बेरोजगार और कम आय वर्ग के लिए रोना और हँसना मना जैसे वाक्य का पर्याय साबित हुआ है।

# 66

लेकिन जैसे नरेंद्र मोदी आज की बात न कर या तो हजार साल पहले की बात करते हैं या आने वाले सौ साल में देश कहा हो सकता है, इसके सपने दिखाते हैं। तो बजट में भी ऐसे ही दूर के सपने दिखाए गए हैं। 10,000 करोड़ रुपए के बायोफार्मा शक्ति प्रोग्राम से लेकर इंडिया सेमी कंडक्टर मिशन 2.0 के तहत सेमी कंडक्टर की महत्वाकांक्षाओं का विस्तार, 40,000 करोड़ की इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स स्कीम, और कई सेक्टरों में मैयुटेक्नरिंग इंसेंटिव जैसी बातें निर्मला सीतारमण के भाषण में छई रही। लेकिन ग्रामीण भारत के मजदूर-किसान, बेरोजगार युवा, छोटे और मध्यम कारोबारी, गृहणियां जिन रोजमर्रा के संकटों से दो-चार होती हैं, उस पर बजट लगभग खामोश रहा। सरकार मनरेंगा की जगह वीवी जीरामजी कानून लाकर उसके प्रचार के लिए विज्ञापन पर भारी खर्च कर रही है। लेकिन बजट भाषण में इस बारे में चुपिी बता रही है।

मोदी सरकार ने एक बार एक ऐसा बजट पेश किया है, जिसमें आम जनता के लिए कुछ नहीं है, जबकि धनपतियों के लिए पूरा मौका है कि वे अपनी तिजोरों का धन दोगुना-चौगुना कर लें। अमेरिका की तरफ से पड़ै टैरिफ की मार और बदलते भू राजनीतिक समीकरणों के बीच मोदी सरकार के पास बजट के रूप में एक अच्छा मौका था, जब वह आम आदमी की चिंता को सीधे संबोधित करती और उसकी रोजमर्रा की समस्याओं का हल पेश करती। लेकिन जैसे नरेंद्र मोदी आज की बात न कर या तो हजार साल पहले की बात करते हैं या आने वाले सौ साल में देश कहा हो सकता है, इसके सपने दिखाते हैं। तो बजट में भी ऐसे ही दूर के सपने दिखाए गए हैं। 10,000 करोड़ रुपए के बायोफार्मा शक्ति प्रोग्राम से लेकर इंडिया सेमी कंडक्टर मिशन 2.0 के तहत सेमी कंडक्टर की महत्वाकांक्षाओं का विस्तार, 40,000 करोड़ की इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स स्कीम, और कई सेक्टरों में मैयुटेक्नरिंग इंसेंटिव जैसी बातें निर्मला सीतारमण के भाषण में छई रही। लेकिन ग्रामीण भारत के मजदूर-किसान, बेरोजगार युवा, छोटे और मध्यम कारोबारी, गृहणियां जिन रोजमर्रा के संकटों से दो-चार होती हैं, उस पर बजट लगभग खामोश रहा। सरकार मनरेंगा की जगह वीवी जीरामजी कानून लाकर उसके प्रचार के लिए विज्ञापन पर भारी खर्च कर रही है। लेकिन बजट भाषण में इस बारे में चुपिी बता रही है।

हुई। इससे संपन्न व्यावसायिक किसानों को तो फायदा हो सकता है, लेकिन उन अनाज किसानों के लिए सीधे तौर पर किसी मदद की बात नहीं की गई जो भारत की खाद्य सुरक्षा की रीढ़ हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य, खेती में बढ़ती लागत या फसलों की कीमतों में उतार-चढ़ाव जैसे मुद्दों का भाषण में कोई जिक्र नहीं था। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सही कहा है कि यह

कमजोर आर्थिक वर्ग और अल्पसंख्यक समुदायों को कोई सहयता दी गई है। मोदी सरकार हर साल नए तरह के सपने बजट में दिखाती है और पिछले सपनों को भूल जाती है। जैसे अब मेक इन इंडिया पर कोई बात नहीं होती। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में किताब घोटाला हुआ, यह हाल ही में आई रिपोर्ट्स से पता चलता है। महिला सशक्तिकरण की बात करने वाली



बजट देश की समस्याओं से आंख मूंदने वाला है। राहुल गांधी ने लिखा कि देश में युवा बेरोजगार हैं, उत्पादन गिर रहा है, निवेशक पूंजी बाहर निकाल रहे हैं, घरेलू बचत तेजी से घट रही है और किसान संकट में हैं। वैश्विक स्तर पर आने वाले झटकों का खतरा मंडरा रहा है, लेकिन बजट इन सभी मुद्दों को नजर अंदाज करता है और आंखें मूंदने वाला है। उन्होंने कहा कि यह ऐसा बजट है जो सुधार से इनकार करता है और भारत के असली संकटों के प्रति अंधा बना हुआ है। हकीमन नहीं है कि इस बजट में देश में अमीरों और गरीबों के बीच बढ़ चुकी आर्थिक असमानता पर कोई चिंता नहीं व्यक्त की गई है और न ही एएसटी, एस्टी, ओबीसी,

सरकार के बजट में न महिलाओं के लिए कोई बड़ी पहल है, न इस बात को चिंता कि रोजगार में महिलाओं की भागीदारी कैसे बढ़ई जाए। बजट में स्मए की गिरती कीमत, महंगाई, या टैरिफ के कारण रहे व्यापार घाटे की भी कोई चिंता नहीं है। मोदी सरकार का मकसद हर तरह से चुनावी राज्यों को साधना होता है, पिछले साल बिहार पर सारा फोकस था, इस बार तमिलनाडु, केरल आदि पर फोकस है। प्रसंगवश बता दें कि निर्मला सीतारमण ने, तमिलनाडु की कॉन्ग्रेस साड़ी पहनकर ही बजट पढ़ा, पिछली बार उन्होंने मधुवनी पेंटिंग वाली साड़ी पहनी थी। इस बार के बजट में निर्मला सीतारमण ने ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में रेशर अर्थ कॉरिडोर बनाने

# मदर ऑफ ऑल डीलस को कैसे प्रभावी बनाए सरकार



भारत ने यूरोपीय संघ को 102 सेवा उप-क्षेत्रों में पहुंच प्रदान की है, जबकि यूरोपीय संघ ने भारत को 144 उप-क्षेत्रों में अवसर दिए हैं, जिनमें वित्तीय, समुद्री और दूरसंचार सेवाएं शामिल हैं। अनुमान है कि यह समझौता 2032 तक यूरोपीय संघ के भारत में निर्यात को दोगुना कर देगा। साथ ही, यह अमरीकी टैरिफ के प्रभाव को कम करने में मदद करेगा, जहां भारत के श्रम-गहन निर्यात प्रभावित हो रहे हैं। माना जा रहा है कि यह समझौता आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया योजनाओं के साथ तालमेल बैठाना है। यह न केवल निर्यात को बढ़ाएगा, बल्कि प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, निवेश और रोजगार सृजन को भी प्रोत्साहित करेगा। उदाहरण के लिए, यूरोपीय संघ के साथ समझौता भारतीय एम.एस.एम.ई. को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में शामिल होने का अवसर देगा। हालांकि, इसके लाभों को अधिकतम करने के लिए चुनौतियों का सामना करना होगा। यहां जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त प्रोफेसर अरुण कुमार की चेतावनियां प्रासंगिक हैं। प्रोफेसर कुमार, जो काले धन और आर्थिक नीतियों के विशेषज्ञ हैं, ने भारत-यूरोपीय संघ एफ.टी.ए. को अमरीका जैसा एक और जाल बताया है। उन्होंने असमान शर्तों, घरेलू उद्योगों विशेषकर कृषि और डेयरी पर जोरिखम, व्यापार घाटे में वृद्धि, नीति स्थान की हानि और दीर्घकालिक आर्थिक निर्भरता की चेतावनी दी है। उन्होंने अमरीकी व्यापार समझौतों से सबक लेने की सलाह दी है, जहां कृषि बाजार खोलने की मांग भारत के लिए कठिन है।

विनीत नारायण भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता, जिसे मदर ऑफ ऑल डीलस के रूप में जाना जा रहा है, लगभग 2 दशकों की लंबी वाताओं का परिणाम है और इसमें 2 अरब से अधिक की आबादी तथा 27 ट्रिलियन डॉलर की संयुक्त अर्थव्यवस्था शामिल है, जो वैश्विक जी.डी.पी. का लगभग 25 प्रतिशत है। यह समझौता भारत की आर्थिक महत्वाकांक्षाओं को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का अवसर प्रदान करती है, विशेषकर ऐसे समय में, जब अमरीकी टैरिफ के कारण निर्यात प्रभावित हो रहा है। हालांकि, इसे प्रभावी बनाने के लिए सरकार को रणनीतिक कदम उठाने

होंगे। इस समझौते के तहत यूरोपीय संघ भारत में निर्यात होने वाले 96.6 प्रतिशत सामानों पर टैरिफ को समाप्त या कम करेगा, जिससे यूरोपीय कंपनियों को सालाना लगभग 4 बिलियन यूरो (लगभग 4.7 बिलियन डॉलर) की बचत होगी। भारत ने यूरोपीय संघ को 102 सेवा उप-क्षेत्रों में पहुंच प्रदान की है, जबकि यूरोपीय संघ ने भारत को 144 उप-क्षेत्रों में अवसर दिए हैं, जिनमें वित्तीय, समुद्री और दूरसंचार सेवाएं शामिल हैं। अनुमान है कि यह समझौता 2032 तक यूरोपीय संघ के भारत में निर्यात को दोगुना कर देगा। साथ ही, यह अमरीकी टैरिफ के प्रभाव को कम करने में मदद करेगा, जहां भारत के श्रम-

गहन निर्यात प्रभावित हो रहे हैं। माना जा रहा है कि यह समझौता आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया योजनाओं के साथ तालमेल बैठाना है। यह न केवल निर्यात को बढ़ाएगा, बल्कि प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, निवेश और रोजगार सृजन को भी प्रोत्साहित करेगा। उदाहरण के लिए, यूरोपीय संघ के साथ समझौता भारतीय एम.एस.एम.ई. को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में शामिल होने का अवसर देगा। हालांकि, इसके लाभों को अधिकतम करने के लिए चुनौतियों का सामना करना होगा। यहां जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त प्रोफेसर अरुण कुमार की चेतावनियां प्रासंगिक हैं।

प्रोफेसर कुमार, जो काले धन और आर्थिक नीतियों के विशेषज्ञ हैं, ने भारत-यूरोपीय संघ एफ.टी.ए. को अमरीका जैसा एक और जाल बताया है। उन्होंने असमान शर्तों, घरेलू उद्योगों विशेषकर कृषि और डेयरी पर जोरिखम, व्यापार घाटे में वृद्धि, नीति स्थान की हानि और दीर्घकालिक आर्थिक निर्भरता की चेतावनी दी है। उन्होंने अमरीकी व्यापार समझौतों से सबक लेने की सलाह दी है, जहां कृषि बाजार खोलने की मांग भारत के लिए कठिन है। इन चेतावनियों को ध्यान में रखते हुए, सरकार को रचनात्मक कदम उठाने चाहिए। सबसे पहले, संवेदनशील क्षेत्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करें। समझौते में

पहुंच, कौशल विकास और निर्यात प्रशिक्षण प्रदान करें। यूरोपीय संघ के साथ संयुक्त निवेश कोष स्थापित करें जो प्रौद्योगिकी हस्तांतरण पर केंद्रित हो, ताकि मेक इन इंडिया मजबूत हो सके। तीसरा, पर्यावरण और सरस्टेनबिलिटी मानकों का अनुपालन। यूरोपीय संघ का कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म (सी.बी.ए.एम.), जो 1 जनवरी, 2026 से पूर्ण रूप से लागू है, भारतीय स्टील और एल्यूमीनियम पर कार्बन टैक्स लगा सकता है, जिससे निर्यातकों को 22 प्रतिशत तक कीमत कम करनी पड़ सकती है। सरकार को नवीकरणीय ऊर्जा में निवेश बढ़ाकर, जैसे कि 500 जी.डब्ल्यू. सौर लक्ष्य की दिशा में तेजी से आगे बढ़कर, इस चुनौती का सामना करना चाहिए। यूरोपीय संघ के साथ संयुक्त हरित प्रौद्योगिकी परियोजनाएं शुरू करें। चौथा, व्यापार घाटे को संतुलित करने के लिए विविधीकरण। सरकार निर्यात को बढ़ावा देने के लिए ए बाजारों की तलाश करें, जैसे कि अफ्रीका और लातीनी अमरीका। साथ ही, समझौते के तहत निवेश नियमों को मजबूत करें ताकि नीति स्थान सुरक्षित रहे। राष्ट्रीय निवेश बोर्ड को सक्रिय करें जो विदेशी निवेश की समीक्षा करे और राष्ट्रीय हितों की रक्षा करे।

# पहले सत्ता लोगों से डरती थी, अब लोग सत्ता से

क्योंकि तब सत्ता करीब महसूस होती थी, ज्यादा मानवीय और कम डराने वाली। जब कोविड आया, तो कई लोगों को लगा कि वह पल फिर से लौट आया है। सड़कें खाली थीं। सायरन खामोश हो गए। लाल बतियां हटा दी गईं। काफिले गायब हो गए। नेताओं ने सादगी, समानता और सांझा दुख की बात की। वादे किए गए-कि कोई सड़क नहीं रोकी जाएगी, कोई वी.आई.पी. कल्चर नहीं होगा, सुरक्षा का कोई नाटक नहीं होगा। ओर फिर, धीरे-धीरे और उम्मीद के मुताबिक, वह सब वापस आ गया। आज, वह नजारा फिर से जाना-पहचाना है-पायलट कारें, पुलिस के वाहन, चमकती लाइटें, अचानक सड़कों का बंद होना और मामूली पदाधिकारियों के लिए भी लंबे काफिले। नौकरशाह, जो कभी खुद गाड़ी चलाते थे, अब अंगरक्षकों के साथ चलते हैं। सादगी की बात करने वाले राजनेता 10 गाडियों के साथ आते हैं। कोविड ने वी.आई.पी. कल्चर का इलाज नहीं किया, बस उसे कुछ देर के लिए रोक दिया था। असहज करने वाला सवाल यह है-क्या वह पुराना, सरल समय कभी लौटेगा? ईमानदार जवाब यह है कि सत्ता, जिसका स्वाद एक बार चख लिया जाए, वह खुद से कभी विनम्र नहीं होती। सुरक्षा सिर्फ इसलिए नहीं बढ़ी क्योंकि खतरे बढ़ गए। यह इसलिए बढ़ी क्योंकि हक जताने की भावना बढ़ गई। सत्ता की हर परत यह मानने लगी कि वह सुरक्षा, प्राथमिकता और रास्ता साफ पाने की हकदार है। जब एक व्यक्ति के लिए सड़कें रोकी जाती हैं, तो हजारों लोगों को पदानुक्रम में उनकी जगह याद दिलाई जाती है। जब काफिले को निकालने के लिए एम्बुलेंस फंस जाती है, तो जनता का गुस्सा चुपचाप पनपता है।



रास्ता साफ पाने की हकदार है। जब एक व्यक्ति के लिए सड़कें रोकी जाती हैं, तो हजारों लोगों को पदानुक्रम में उनकी जगह याद दिलाई जाती है। जब काफिले को निकालने के लिए एम्बुलेंस फंस जाती है, तो जनता का गुस्सा चुपचाप पनपता है। जब राजनेता बिना सुरक्षा परतों के लोगों के बीच नहीं चल सकते, तो विश्वास कम हो जाता है। सिस्टम नागरिकों से कहता है कि वह समानता में विश्वास रखता है लेकिन उसके कार्य कुछ और ही करते हैं। क्या यह कभी बदलेगा? यह बदल सकता है लेकिन केवल दबाव में, सद्भावना से नहीं। बदलाव इसलिए नहीं आएगा कि नेता अचानक विनम्र हो जाएँ। यह केवल तभी आएगा जब मतदाता लगातार फिजूलखर्ची को बँडन करेंगे, जब अदालतें सुरक्षा श्रेणियों को सख्ती से सीमित करेंगी, जब मॉडिया कफिलों का महिमामंडन करना बंद कर देगा, और जब नागरिक वी.आई.पी. आवाजाही के कारण होने वाली असुविधा को सामान्य मानना बंद कर देंगे। कुछ राज्यों ने सुरक्षा सूचियों में कटौती करने की कोशिश की है। कुछ नेताओं ने जानबूझकर अपने तामझाम

को कम किया है। लेकिन ये अपवाद हैं, नियम नहीं। वी.आई.पी. कल्चर इसलिए जीवित है क्योंकि समाज इसे सहन करता है। हम निजी तौर पर शिकायत करते हैं लेकिन सार्वजनिक रूप से पालन करते हैं। हम अपने जीवन को ढाल लेते हैं और सिस्टम इस खामोशी को सहमति मान लेता है। अकेले चलते हुए राजनेता की पुरानी छवि इसलिए काम करती थी क्योंकि तब सत्ता लोगों से डरती थी। आज, लोग सत्ता से डरते हैं। वही असली बदलाव है। क्या इसे बदला जा सकता है? शायद, लेकिन केवल तभी, जब सत्ता को सायरन और बैरिकेड्स के माध्यम से मांग करने की बजाय फिर से सम्मान अर्जित करने के लिए मजबूर किया जाए। केवल तभी, जब सार्वजनिक सेवा फिर से सेवा लगे, राजशाही नहीं। साथ ही, इन नए बने की चाह रखने वाले राजनेताओं की असुखा भी है, जिन्हें तभी पहचाना जाएगा जब उनके साथ 6 बॉडीगार्ड हों। यह तब होता है, जब आप एक हलचल पैदा करना चाहते हैं कि मैं आ गया हूँ। यह अद्भुत है कि कुछ शक्तिशाली और सरल मंत्री अभी भी अपने साथ किसी को लेकर नहीं चलते। तब तक, काफिले लंबे होते रहेंगे, लाल बतियां चमकती रहेंगी और सड़कें रुकती रहेंगी और हम चुपचाप पूछते रहेंगे-शासकों ने हमारे बीच चलना कब बंद कर दिया और हमारे ऊपर से गुजरना कब शुरू कर दिया? वह सवाल, किसी भी सायरन से ज्यादा, सत्ता में बैठे लोगों को चिंतित करना चाहिए। 2014 में जब नई सरकार ने शपथ ली थी, तो हमने सुना था कि कोई सायरन नहीं होगा, कोई लाल बत्ती नहीं होगी, सुरक्षा गार्ड नहीं होंगे लेकिन साहब न कहीं कुछ गलत हो गया है। असली राजनेता के लिए असली खतरा समझ में आता था लेकिन अब यह अराइड्ट सिंड्रोम (पहुंच जाने का भ्रम) बन गया है-बॉडीगार्ड लो, बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट और वी.आई.पी. सिंड्रोम दरअसल आम आदमी के लिए एक उत्पीडन है। सबसे बढ़कर, हम अक्सर ऐसे धोखेबाजों और व्यक्तियों को देखते हैं, जो अभी-अभी जेल से बाहर आए हैं और इन निजी सुरक्षा गार्डों के साथ घूमते हैं। यह एक बहुत ही दुखद मजाक है।

देवी एम. चेरियन एक समय था, ज्यादा पुरानी बात नहीं, जब राजनेता बिना किसी चेतावनी के बाजारों में चले आते थे। जब एक जिला कलेक्टर बस स्टैंड पर खड़ा होता था। जब किसी मंत्री की गाड़ी लाल बत्ती पर बाकी सब की तरह इंतजार करती थी। सत्ता का अस्तित्व था, लेकिन उसे अपनी मौजूदगी का एंशन करने के लिए सायरन की जरूरत नहीं थी। लोग उस समय को सिर्फ पुरानी यादों के तौर पर नहीं, बल्कि एक चाहत के साथ याद करते हैं। क्योंकि तब सत्ता करीब महसूस होती थी, ज्यादा मानवीय और कम डराने वाली। जब कोविड आया, तो कई लोगों को लगा कि वह पल फिर से लौट आया है। सड़कें खाली थीं। सायरन खामोश हो गए। लाल बतियां हटा दी गईं। काफिले गायब हो गए। नेताओं ने सादगी, समानता और सांझा दुख की बात की। वादे किए गए-कि कोई सड़क नहीं रोकी जाएगी, कोई वी.आई.पी. कल्चर नहीं होगा, सुरक्षा का कोई नाटक नहीं होगा। ओर फिर, धीरे-धीरे और उम्मीद के मुताबिक, वह सब वापस आ गया। आज, वह नजारा फिर से जाना-पहचाना है-पायलट कारें, पुलिस के वाहन, चमकती लाइटें, अचानक सड़कों का बंद होना और मामूली पदाधिकारियों के लिए भी लंबे काफिले। नौकरशाह, जो कभी खुद गाड़ी चलाते थे, अब अंगरक्षकों के साथ चलते हैं। सादगी की बात करने वाले राजनेता 10 गाडियों के साथ आते हैं। कोविड ने वी.आई.पी. कल्चर का इलाज नहीं किया, बस उसे कुछ देर के लिए रोक दिया था। असहज करने वाला सवाल यह है-क्या वह पुराना, सरल समय कभी लौटेगा? ईमानदार जवाब यह है कि सत्ता, जिसका स्वाद एक बार चख लिया जाए, वह खुद से कभी विनम्र नहीं होती। सुरक्षा सिर्फ इसलिए नहीं बढ़ी क्योंकि खतरे बढ़ गए। यह इसलिए बढ़ी क्योंकि हक जताने की भावना बढ़ गई। सत्ता की हर परत यह मानने लगी कि वह सुरक्षा, प्राथमिकता और रास्ता साफ पाने की हकदार है। जब एक व्यक्ति के लिए सड़कें रोकी जाती हैं, तो हजारों लोगों को पदानुक्रम में उनकी जगह याद दिलाई जाती है। जब काफिले को निकालने के लिए एम्बुलेंस फंस जाती है, तो जनता का गुस्सा चुपचाप पनपता है।



लखनऊ, (संवाददाता)। उत्तर प्रदेश को वैश्विक निवेश मानचित्र पर मजबूती से स्थापित करने की दिशा में राज्य सरकार के प्रयासों को विदेशी निवेशकों से निरंतर समर्थन मिल रहा है। सिंगापुर की अग्रणी एकीकृत कंटेनर लॉजिस्टिक्स कंपनी एपी मोलर माएस्क के प्रबंध निदेशक रिन पील पेडरसन ने सोमवार को लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भेंट की। इस दौरान उत्तर प्रदेश में निवेश विस्तार को लेकर गहन चर्चा हुई। पेडरसन के साथ विवेक शर्मा, हेड बिजनेस डेवलपमेंट एवं रेगुलेटरी अफेयर्स भारत, बांग्लादेश एवं श्रीलंका क्षेत्र भी मौजूद रहे। बैठक के दौरान उत्तर प्रदेश में निवेश की व्यापक संभावनाओं, उद्योगों के लिए अनुकूल कारोबारी माहौल तथा राज्य सरकार की निवेश प्रोत्साहन नीतियों पर विस्तार से चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश देश के सबसे तेजी से विकसित हो रहे राज्यों में शामिल है और यहां निवेशकों के लिए सुरक्षित, स्थिर और पारदर्शी वातावरण उपलब्ध कराया जा रहा है। सिंगल विंडो सिस्टम, त्वरित स्वीकृतियां, नीति आधारित प्रोत्साहन और मजबूत कानून व्यवस्था के माध्यम से सरकार निवेशकों को हर स्तर पर सहयोग दे रही है।

# टी20 विश्व कप का काउंटडाउन शुरू सूर्यकुमार रच पाएंगे कीर्तिमान

**नई दिल्ली।** टी20 विश्व कप की तैयारियां पूरी हो गई हैं और सभी 20 टीमों इसमें हिस्सा लेने के लिए तैयार हैं। इस वैश्विक टूर्नामेंट की मेजबानी भारत और श्रीलंका कर रहे हैं। आइए देखते हैं सभी टीमों का स्क्वाड टी20 विश्व कप का काउंटडाउन शुरू हो गया है और अब इस वैश्विक टूर्नामेंट को शुरू होने में पांच दिन का समय शेष रह गया है। भारतीय टीम इस टूर्नामेंट में खिताब बचाने के इरादे से उतरेगी। सभी 20 टीमों ने अपने स्क्वाड घोषित कर दिए हैं और प्रत्येक टीम टी20 विश्व कप में अपना दम दिखाने के लिए तैयार है। आइए जानते हैं कौन-कौन सी टीमों इसमें हिस्सा ले रही हैं। 20 टीमों ले रही हिस्सा पिछले बार की तरह इस बार भी टी20 विश्व कप में 20 टीमों हिस्सा ले रही हैं। इन सभी टीमों को चार

मुंबई, चेन्नई, कोलकाता और अहमदाबाद इस टूर्नामेंट के मैचों की मेजबानी करेगी। वहीं, कोलंबो का आर प्रेमादासा और एस स्पोर्ट्स क्लब में मैच होंगे, जबकि कैंडी का पल्लेकेले इंटरनेशनल स्टेडियम भी मैच की मेजबानी करेगा। सूर्यकुमार के पास उपलब्धि हासिल करने का मौका भारतीय

हरमीत सिंह, नोस्ट्रुश केनजिंगे, शैडली वान शकविक, सौरभ नेत्रावलकर, अली खान, मोहम्मद मोहसिन, शुभम रंजने नामीबिया: गेरेहाई इरास्मस (कप्तान), जेन ग्रीन, बर्नाई शोल्ड्रज, रुबेन ट्रम्पेलेमैन, जे.जे स्मिथ, जान फ्राइलिनक, लॉरेन स्टीनकैप, मालन क्रूगर, निकोलो लोफ्टी-ईंटन, जैक ब्रासेल, बेन शिकोंगो, जेसी बाल्ट, डायलन लीचर, डब्ल्यूपी मायबर्ग, मैक्स हेंगो। ट्रेवलिंग रिजर्व: अलेक्जेंडर वोल्थीक। नीदरलैंडः स्काॉट एडवर्ड्स (कप्तान), कॉलिन एकरमैन, नोआ

मसाकाद्जा, टोनी मुनयोंगा, ताशिांगा मुसेकिवा, ब्लेसिंग मुजाराबानी, डायोन मायर्स, रिचर्ड नगारवा, ब्रेंडन टेलर। आयरलैंड: पॉल स्टर्लिंग (कप्तान), मार्क एडायर, रॉस एडायर, बेन कैलिट्ज़, कर्टिस कैम्फर, गैरेथ डेलानी, जॉर्ज डॉकरेल, मैथ्यू हम्फ्रीज, जोश लिटिल, बैरी मैकार्थी, हैरी टेक्टर, टिम टेक्टर, लोरकान टकर, बेन व्हाइट, क्रो गयंग। ओमान: जतिंदर सिंह (कप्तान), विनायक शुक्ला, मोहम्मद नदीम, शकील अहमद, हम्माद मिर्जा, वसीम अली, करण सोनावले, शाह फैसल, नदीम खान, सुफियां महमूद, जय ओडेदरा, शफीक जान, आशीष ओडेदरा, जितेन रामानंदी, आमिर कलीम। इंग्लैंड: हैरी ब्रूक (कप्तान), रेहान अहमद, जोफ्रा आर्चर, टॉम बैटन, जैकब बथेल, जोस बटलर, सैम कॉनन, लियाम डॉसन, बेन डकेट, विल जैक्स, जेमी ओवरटन, आदिल राशिद, फिल सॉल्ट, जोश टॉग, ल्यूक वुड। वेस्टइंडीज: शाई होप (कप्तान), शिमरॉन हेल्मायर, जॉनसन चावर्स, रोस्टन चेज, मैथ्यू फोर्ड, जेसन होल्डर, अकील हुसैन, शमार जोसेफ, ब्रैंडन किंग, गुडाकिश मोती, रोवमैन पोवेल, शेरफेन रदरफोर्ड, क्वेंटिन सैम्सन, जेडन सौल्स, रोमारियो शेफर्ड'। इटली: वेन मीडसेन (कप्तान), मार्कस कैपोपियानो, जियान पिपेरो मीडे, जाएन अली, अली हसन, क्रिसन जॉर्ज कलुगामागे, हैरी मैनेटी, एंथोनी मोस्का, जस्टिन मोस्का, सैयद नकवी, बेंजामिन मैनेंटी, जसप्रीत सिंह, जे.जे स्मट्स, ग्रांट स्टीवर्ट, थॉमस ड्रेका। नेपाल: रोहित पौडेल (कप्तान), दीपेंद्र सिंह ऐरी, संदीप लामिछाने, कुशल भुर्तेल, आसिफ शेख, संदीप जोरा, आरिफ शेख, बसीर अहमद, सोमपाल कामी, करण केसी, नंदन यादव, गुलशन झा, ललित राजवंशी, शेर मल्ला, लोकेश बम। स्कॉटलैंड: मापोसा, तदिवानाशे मारुमनी, वेलिंगटन

ब्रैडली करी, ओलिवर डेविडसन, क्रिस ग्रीव्स, जागुल्लाह एहसान, माइकल जोंस, माइकल लीस्क, फिनले मैकक्रैथी, ब्रैंडन मैकमुलन, जॉर्ज मुन्सी, सफयान शरीफ, मार्क वाट, ब्रैडली व्हील। ट्रेवलिंग रिजर्व: जैसपर डेविडसन, जैक जॉर्जिस। दक्षिण अफ्रीका: एडेन मार्करैम (कप्तान), कॉर्बिन बोश, डेवाल्ड ब्रेविस, विक्टन डिकॉक, मार्को यानसेन, जॉर्ज लिंडे, केशव महाराज, क्वेना मफाका, डेविड मिलर, लुंगी एंगिगडी, एनरिक नॉल्ड, कमिसो रबाडा, रेयान रिक्लेटन, जेसन स्मिथ, ट्रिस्टन स्टब्स। न्यूजीलैंड: मिचेल सैंटनर (कप्तान), फिन एलन, माइकल ब्रैसवेल, मार्क चार्लेम, डेवोन कॉर्नवे, जैकब डफ्नी, लॉकी फर्ग्यूसन, मैट हेनरी, काइल जैमीसन, डेरिल मिचेल, जेम्स नीशाम, ग्लेन फिलिप्स, रचिन रविंद्र, टिम सीफर्ट, ईश सोढ़ी। अफगानिस्तान: राशिद खान (कप्तान), नूर अहमद, अब्दुल्ला अहमदजई, सेदिकुल्लाह अटल, फजल हक फारूकी, रहमानुल्लाह गुरबाज, नवीन उल हक, मोहम्मद इशाक रहीमी, शाहिदुल्लाह कमाल, मोहम्मद नबी, गुलबदीन नैब, अजमतुल्लाह उमरजई, मुजीब उर रहमान, दरविश रसूली, इब्राहिम जादरान। रिजर्व: एएम गजनफर, एजाज अहमद अहमदजई, जिया उर रहमान शरीफी। कनाडा: दिलप्रीत बाजवा (कप्तान), अजयवीर हुंदल, अंश पटेल, दिलोन हेडलिंगर, हर्ष ठांकेर, जसकरनदीप बुदुर, कलीम सना, कंवरपाल तायथुर, नवीनत धालीवाल, निकोलस किर्टन, रविंदरपाल सिंह, साद बिन जफर, शिवम शर्मा, श्रेयस मोव्वा, युवराज समरा। यूएई: मोहम्मद वसीम (कप्तान), अलीशान शराफू, आर्शांश शर्मा, ध्रुव पाराशर, हैदर अली, हर्षित कौशिक, जुनैद सिद्दीकी, मयंक कुमार, मुहम्मद अरफान, मोहम्मद फारूक, मोहम्मद जवाबुल्लाह, मोहम्मद जोहैब, रोहिद खान, सोहैब खान, सिमरनजीत सिंह।

टी20 विश्व कप 2026			
ग्रुप ए	ग्रुप बी	ग्रुप सी	ग्रुप डी
<ul style="list-style-type: none"> <li>भारत</li> <li>पाकिस्तान</li> <li>अमेरिका (यूएसए)</li> <li>नीदरलैंड्स</li> <li>नामीबिया</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ऑस्ट्रेलिया</li> <li>श्रीलंका</li> <li>आयरलैंड</li> <li>जिम्बाब्वे</li> <li>ओमान</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>इंग्लैंड</li> <li>वेस्टइंडीज</li> <li>स्कॉटलैंड</li> <li>नेपाल</li> <li>इटली</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>न्यूजीलैंड</li> <li>द. अफ्रीका</li> <li>अफगानिस्तान</li> <li>कनाडा</li> <li>संयुक्त अरब अमीरात (यूएई)</li> </ul>

कप्तान सूर्यकुमार यादव के पास टी20 विश्व कप के दौरान उपलब्धि हासिल करने का मौका रहेगा। अगर भारतीय टीम खिताब जीतने में सफल रही तो सूर्यकुमार भारत के चौथे कप्तान होंगे जिन्होंने आईसीसी ट्रॉफी जीती है। भारत के लिए अब तक कपिल देव ( 1983 वनडे विश्व कप), महेंद्र सिंह धोनी ( 2007 टी20 विश्व कप, 2011 वनडे विश्व कप और 2013 चैंपियंस ट्रॉफी) और रोहित शर्मा ( 2024 टी20 विश्व कप और 2025 चैंपियंस ट्रॉफी) ने ही भारत को अपनी कप्तानी में आईसीसी खिताब दिलाए हैं। आइए देखते हैं सभी 20 टीमों का पूरा स्क्वाड भारत: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, संजु सैमसन, शिवम दुबे, ईशान किशन, हार्दिक पांड्या, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह, हर्षित राणा, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, रिंकू सिंह। अमेरिका: मोनांक पटेल (कप्तान), जेसी सिंह, एंड्रौज गौस, शेहान जयसूर्या, मिलिंद कुमार, शयान जहांगीर, साईतेजा मुक्कामाला, संजय कृष्णमूर्ति,

क्रोज, बास डी लीडे, जैक एरॉन दत्त, फ्रेड क्लासेन, काइल क्लेन, माइकल लेविट, जैक लायन-कैशेट, मैक्स ओ'डोड, लोगान वैन बीक, टिम वैन डेर गुगटेन, रूलोफ वैन डेर मेरेवे, पॉल वैन मीकेने, शाकिब जुल्फिकार। पाकिस्तान: सलमान अली आगा (कप्तान), अबरार अहमद, बाबर आजम, फहीम अशरफ, फखर जमां, ख्वाजा मोहम्मद नफे, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद सलमान मिर्जा, नसीम शाह, साहिबजादा फरहान, सईम अयूब, शाहीन शाह अफरीदी, शादाब खान, उस्मान खान, उस्मान तारिक। ऑस्ट्रेलिया: मिचेल मार्श (कप्तान), जैविश बार्टलेट, कूपर कॉनोली, टिम डेविड, बेन ड्वारशुइस, कैमरन ग्रीन, नाथन एलिस, जोश हेजलवुड, ट्रेविथ हेड, जोश इंग्लिस, मैथ्यू कुहनेमैन, ग्लेन मैक्सवेल, मैथ्यू रे नशां, मार्कस स्टोइनिंस, एडम जांपा। जिम्बाब्वे: सिकंदर रजा (कप्तान), ब्रायन बेनेट, रयान बर्ल, ग्रीम क्रेमर, ब्रेडली इवांस, क्लाइव मवांडे, टिनोटेंडा मापोसा, तदिवानाशे मारुमनी, वेलिंगटन

## पहले अंडर-19 टीम ने औंधे मुंह पटका, अब सीनियर टीम का सामना करने का साहस नहीं!

**नई दिल्ली।** पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ टी20 विश्व कप में खेलने से इनकार कर दिया है। हालांकि, उनकी टीम अंडर-19 विश्व कप में भारत के खिलाफ खेली थी। यह साबित करता है कि भारत को लेकर पाकिस्तान ने किस तरह दोहरा रवैया अपनाया है। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला और इस तरह भारत हमेशा पाकिस्तान पर भारी पड़ा है। टी20 विश्व कप की शुरुआत अगले पांच दिनों में होने जा रही है। टूर्नामेंट शुरू होने से पहले ही विवादों में धिर गया है। पहले बांग्लादेश के कारण विश्व कप विवादों में रहा और अब पाकिस्तान इसकी चमक फीकी करने की कोशिशों में जुटा हुआ है। भारत और पाकिस्तान की टीमों आईसीसी टूर्नामेंट्स में ही एक दूसरे का सामना करती हैं, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो सकेगा क्योंकि पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ खेलने से मना कर दिया है। हालांकि, बहिष्कार की नौटंकी करने वाला पाकिस्तान इस मामले पर दोहरा रवैया अपना रहा है। पाकिस्तानी सरकार ने लिया फैसला बांग्लादेश को टी20 विश्व कप से बाहर करने के बाद पाकिस्तान आईसीसी को आंखें दिखा रहा था। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) के अध्यक्ष मोहम्मिन नकवी ने कहा था कि विश्व कप में खेलने का फैसला पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ करेंगे। नकवी ने हाल ही में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से मुलाकात भी की थी। पाकिस्तानी सरकार ने रविवार को राष्ट्रीय टीम को विश्व कप में खेलने की मंजूरी दे

दी। सरकार ने हालांकि, इस बात का एलान किया कि पाकिस्तान की टीम भारत के खिलाफ होने वाले ग्रुप चरण के मैच का बहिष्कार करेगी। भारत ने पाकिस्तान को अंडर-19 विश्व कप से किया बाहर पाकिस्तान ने जब भारत के खिलाफ टी20 विश्व कप मैच का बहिष्कार करने का फैसला लिया, उसी दिन भारतीय अंडर-19 टीम ने पाकिस्तान को विश्व कप से बाहर का रास्ता दिखाया। दरअसल, दोनों टीमों के बीच रविवार को बुलवावो में अंडर-19 विश्व कप का मुकाबला खेला गया। दोनों टीमों के लिए यह मैच काफी अहम था क्योंकि इससे सेमीफाइनल का रास्ता तय होता था। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 49.5 ओवर में 252 रन बनाए। पाकिस्तान की टीम 46.2 ओवर में ही 194 रन पर आउट हो गई। भारतीय टीम ने इस तरह सेमीफाइनल में प्रवेश किया, जबकि पाकिस्तान का सफर अंडर-19 विश्व कप में समाप्त हो गया। अलग टूर्नामेंट के लिए अलग नियम? भारत की युवा टीम से मुह की खाने के तुरंत बाद ही यह खबर आई की पाकिस्तान सरकार ने सीनियर टीम को भारत के खिलाफ खेलने से मना कर दिया है। पाकिस्तान का वहीं से दोहरा चरित्र सामना आ गया क्योंकि अंडर-19 विश्व कप के लिए पाकिस्तान ने अपनी टीम को भारत के खिलाफ खेलने दिया। अब जब 15 फरवरी को भारत और पाकिस्तान की सीनियर टीमों विश्व कप में खेलने की तैयारी कर रही थीं, तो उसने अंतिम समय में बहिष्कार करने की नौटंकी शुरू कर दी। इतना

ही नहीं पिछले साल एशिया कप के दौरान भी पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ मैच खेला था। उस वक्त ना तो पीसीबी ने इसका विरोध किया और ना ही पाकिस्तान की सरकार कुछ बोली। क्या भारत का सामना करने से डर रहा पाकिस्तान सूर्यकुमार यादव की अगुआई वाली भारतीय टीम टी20 में शानदार फॉर्म में चल रही है। भारत ने हाल ही में न्यूजीलैंड के खिलाफ पांच मैचों की टी20 सीरीज 4-1 से अपने नाम की है। इतना ही नहीं, भारत टी20 विश्व कप जीतने का प्रबल दावेदार है और वह इस टूर्नामेंट में खिताब बचाने के इरादे से उतरेगा। भारत का रिकॉर्ड भी विश्व कप में पाकिस्तान के खिलाफ अभूतपूर्व है। दोनों टीमों आठ बार एक दूसरे के सामने आई हैं, जिसमें से सात बार भारत को सफलता मिली है, जबकि सिर्फ एक बार पाकिस्तान जीता है। अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, सूर्यकुमार यादव, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती और हार्दिक पांड्या जैसे भारतीय खिलाड़ी फॉर्म में हैं जो पाकिस्तानी टीम को आसानी से पटखनी दे सकते हैं। ऐसे में वह सवाल उठना लाजिमी है कि भारत की खतरनाक फॉर्म को देखते हुए क्या पाकिस्तान टीम इंडिया का सामना करने से कतरा रहा है? एशिया कप में दी थी पटखनी भारत और पाकिस्तान के बीच पिछले साल से ही रिश्ते काफी तलख चल रहे हैं। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर नाम से सैन्य कार्रवाई की थी और पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया था।

### भारत के खिलाफ विश्वकप मैच का पाकिस्तान का बहिष्कार बेतुका क्यों इससे पहले ये चार देश भी उठा चुके कदम

**नई दिल्ली।** पाकिस्तान की सरकार ने एलान किया है कि उनकी टी20 विश्व कप में भारत के खिलाफ खेले जाने वाले ग्रुप मुक़ाबले का बहिष्कार करेगी। इसके पीछे उनकी तरफ से कारण भी स्पष्ट नहीं किया गया है। हम यहां आपको बताएंगे कि ऐसा पहले कब-कब हुआ है, जब किसी टीम ने विश्व कप मुक़ाबले में खेलने से इनकार किया है। पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने भारत के खिलाफ टी20 विश्व कप 2026 में खेलने से इनकार कर दिया है। रविवार को पाकिस्तान सरकार को तरफ से जानकारी दी गई कि पाकिस्तान टीम आगामी विश्व कप में खेलेंगी, लेकिन 15 फरवरी को भारत के खिलाफ खेले जाने वाले मुक़ाबले का बहिष्कार करेगी। पीसीबी को उसके इस फैसले का अंजाम भी भुगतान पड़ सकता है। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) ने मामले में हस्तक्षेप किया है और उसे पीसीबी से आधिकारिक सूचना मिलने का इंतजार है। अगर पाकिस्तान इस रवैये पर अडिग रहा तो उसके भारी नुक़सान उठाना पड़ सकता है। बेवजह अडिगल रवैया अपना रहा पाकिस्तान यह पहला मौका नहीं है जब किसी टीम ने विश्व कप में मुक़ाबले के बहिष्कार का फैसला लिया है। इससे पहले चार टीमों ऐसा कर चुकी हैं। हालांकि, उन्होंने सुरक्षा के चलते ऐसे फैसले किए। लेकिन पाकिस्तान को अपने सभी मुक़ाबले श्रीलंका में खेलने हैं। 15 फरवरी को होने वाला मुक़ाबला भी कोलंबो में खेला जाना था, अगर पाकिस्तान फ़ाइनल में पहुंचता है तो खिताबी मैच भी श्रीलंका में ही कराया जाएगा। इसके बावजूद पाकिस्तान ने बिना किसी वजह के भारत के खिलाफ मैच के बहिष्कार का एलान कर दिया है। पाकिस्तान पर क्या कड़े फैसले ले सकता है आईसीसी? पाकिस्तान बहिष्कार की नौटंकी कर रहा है, लेकिन उसर इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। आईसीसी ने पाकिस्तान सरकार के इस फैसले पर श्वाल उठाते हुए चेतावनी दी है कि इस बहिष्कार के परिणामस्वरूप दंडात्मक प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं।

### ये हमारा फैसला नहीं, भारत के खिलाफ नहीं खेलने पर सलमान आगा की प्रतिक्रिया जानें क्या कहा

**कराची।** पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा ने भारत के खिलाफ टी20 विश्व कप मैच के बहिष्कार को लेकर बयान दिया है। सलमान का कहना है कि वह और उनकी टीम इस मामले में अपनी सरकार और पीसीबी के निर्देश का पालन करेगी। पाकिस्तान के टी20 कप्तान सलमान अली आगा ने भारत के खिलाफ टी20 विश्व कप में नहीं खेलने पर प्रतिक्रिया दी है।



पाकिस्तानी सरकार ने रविवार को कहा था कि उनकी राष्ट्रीय टीम इस वैश्विक टूर्नामेंट में हिस्सा लेगी, लेकिन भारत के खिलाफ 15 फरवरी को होने

वाले मैच का बहिष्कार करेगी। विश्व कप की शुरुआत सात फरवरी से हो रही है और भारत-पाकिस्तान एक ही ग्रुप में शामिल हैं। मैच के लिए श्रीलंका जाएगी भारतीय टीम भारत और पाकिस्तान के बीच ये मुक़ाबला श्रीलंका के कोलंबो में होना है। हालांकि, पाकिस्तान सरकार ने स्पष्ट किया है कि वह ग्रुप चरण के इस मैच का बहिष्कार करेगी। वहीं, भारतीय टीम ने आईसीसी के प्रोटोकॉल का पालन करने का फैसला किया है और वह इस मैच के लिए श्रीलंका जाएगी। सूत्रों के अनुसार, भारत इस मैच के लिए अभ्यास करेगा और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेगा। टॉस के दौरान सूर्यकुमार यादव मैदान पर मौजूद रहेंगे और टीम इस बात का इंतजार करेगी कि मैच रेफरी मुक़ाबले को रद्द करें। 'सरकार और पीसीबी के निर्देश का करेंगे पालन' भारत के खिलाफ नहीं खेलने के फैसले पर आगा ने कहा कि खिलाड़ी इस बारे में निर्णय नहीं लेते हैं। उन्होंने कहा कि वह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) और पाकिस्तान सरकार के निर्देश का पालन करेंगे। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे टी20 मैच के बाद आगा ने कहा, हम विश्व कप में खेलने जा रहे हैं। ये हमारा फैसला नहीं है और हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। जो भी हमारी सरकार और पीसीबी प्रमुख कहेंगे, हम बस उसका पालन करेंगे। आईसीसी पाकिस्तान की हरकत से नाबुश पाकिस्तान ने टी20 विश्व कप से ठीक पहले ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3-0 से टी20 सीरीज अपने नाम की है।

### ऑस्ट्रेलिया के लिए बढ़ती जा रही मुश्किलें विश्व कप के शुरुआती चरण में हिस्सा नहीं ले पाएगा ये गेंदबाज

**सिडनी।** टी20 विश्व कप की शुरुआत होने में अब कुछ ही दिन का समय शेष रह गया है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के लिए मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। पहले पैट कमिंस टूर्नामेंट से बाहर हुए और अब टीम के एक और अनुभवी तेज गेंदबाज टूर्नामेंट से शुरुआती दौर के लिए ऑस्ट्रेलिया टीम से नहीं जुड़ पाएंगे। ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड टी20 विश्व कप के शुरुआती मैचों के लिए टीम के साथ नहीं जाएंगे। हेजलवुड चोट से उबर रहे हैं और इस वैश्विक टूर्नामेंट के लिए ऑस्ट्रेलियाई टीम का हिस्सा हैं। राष्ट्रीय चयनकर्ता टोनी डोडेमेड ने सोमवार को यह जानकारी दी है। वहीं, नाथन एलिस, टिम डेविड और ग्लेन मैक्सवेल कोलंबो पहुंच चुके हैं। डोडेमेड ने कहा कि ये खिलाड़ी टी20 विश्व कप के लिए मंगलवार को ऑस्ट्रेलियाई टीम से जुड़ेंगे। ऑस्ट्रेलिया को श्रीलंका में खेलने हैं शुरुआती मैच ऑस्ट्रेलिया ग्रुप चरण में अपने चार मैच श्रीलंका में खेलेगा। कंगारू टीम अपने अभियान की शुरुआत 11 फरवरी को आयरलैंड के खिलाफ करेगी। हेजलवुड टूर्नामेंट के शुरुआती दौर में सिडनी में रहेंगे। सीन एबोट ट्रेवल रिजर्व के तौर पर टीम के साथ जाएंगे। हेजलवुड चोट के कारण 2025-26 एशेज सीरीज से भी बाहर रहे थे। डोडेमेड ने यह नहीं बताया कि हेजलवुड कब से खेल सकेंगे। ऑस्ट्रेलिया के प्रारंभिक दौर के मुक़ाबले 20 फरवरी को खत्म होंगे। टी20 विश्व कप भारत और श्रीलंका में सात फरवरी से आठ मार्च तक खेला जाएगा।



### टी20 विश्व कप के अभ्यास मैचों के लिए भारत ए टीम घोषित बदोनी करेंगे कप्तानी

**नई दिल्ली।** टी20 विश्व कप से पहले भारत ए टीम अभ्यास मैच खेलेगी। इसके लिए बीसीसीआई ने टीम का एलान कर दिया है। इस टीम में तिलक वर्मा भी शामिल हैं जो चोट के कारण पिछले कुछ समय से बाहर चल रहे थे। टी20 विश्व कप के अभ्यास मैच के लिए भारत ए टीम घोषित हो गई है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने अमेरिका और नामीबिया के खिलाफ दो अभ्यास मैचों के लिए सोमवार को टीम का एलान किया है।



भारत ए टीम की कप्तान आयुष बदोनी करेंगे। दिलचस्प बात यह है कि चोट के कारण बाहर चल रहे तिलक वर्मा भी इस टीम में शामिल हैं। तिलक

टी20 विश्व कप के लिए भारतीय टीम का हिस्सा हैं। सात फरवरी से शुरू होगा टूर्नामेंट टी20 विश्व कप की शुरुआत सात फरवरी से हो रही है। इस टूर्नामेंट में 20 टीमों हिस्सा ले रही हैं। भारत ने 2024 में दक्षिण अफ्रीका को हराकर खिताब अपने नाम किया था और सूर्यकुमार यादव की अगुआई वाली टीम इस वैश्विक टूर्नामेंट में खिताब का बचाव करने उतरेगी। सिर्फ एक मैच में खेलेंगे तिलक बीसीसीआई ने टीम का एलान करते वक्त बताया कि तिलक वर्मा टी20 विश्व कप के लिए भारतीय टीम से जुड़ने से पहले एक अभ्यास मैच का हिस्सा होंगे। तिलक के पेट की सर्जरी हुई थी जिस कारण वह न्यूजीलैंड के खिलाफ सीमित ओवर की सीरीज का हिस्सा नहीं थे। तिलक बंगलूरू स्थित बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सिलेंस (सीओई) में रिहैब कर रहे हैं और उम्मीद है कि वह जल्द ही टीम से जुड़ेंगे। अब तिलक का नाम भारत ए टीम में शामिल हो गया है जो इस बात के संकेत है कि वह टी20 विश्व कप तक पूरी तरह फिट हो जाएंगे। टी20 विश्व कप के अभ्यास मैच के लिए भारत ए टीम: आयुष बदोनी (कप्तान), निमन दीपर, आशुतोष शर्मा, प्रियांस आर्या, एन जगदीशन (नवक्रीपर), तिलक वर्मा, प्रियाण पाराग, मानव सृथार, अशोक शर्मा, उर्विल पटेल (विकेटकीपर), गुरजपनीत सिंह, विपराज निगम, रवि बिश्नोई, खलील अहमद, मयंक यादव।

### भारत से नहीं खेलने के पाकिस्तान के फैसले पर बीसीसीआई ने दी प्रतिक्रिया

**नई दिल्ली।** भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने पाकिस्तान के भारत के खिलाफ मैच का बहिष्कार करने पर प्रतिक्रिया दी है। शुक्ला का कहना है कि वह इस मामले में आईसीसी से सहमत हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने पाकिस्तान को लेकर प्रतिक्रिया दी है। पाकिस्तान ने टी20 विश्व कप में भारत के खिलाफ ग्रुप चरण का मैच खेलने से इनकार कर दिया है। इस मामले को लेकर आईसीसी ने भी



हस्तक्षेप किया है और उसका कहना है कि वह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) से आधिकारिक सूचना का इंतजार कर रहा है। भारत और पाकिस्तान के बीच 15 फरवरी को कोलंबो में मुक़ाबला खेला जाना है। मैच

के लिए श्रीलंका जाएगी भारतीय टीम भारत और पाकिस्तान के बीच ये मुक़ाबला श्रीलंका के कोलंबो में होना है। हालांकि, पाकिस्तान सरकार ने स्पष्ट किया है कि वह ग्रुप चरण के इस मैच का बहिष्कार करेगी। वहीं, भारतीय टीम ने आईसीसी के प्रोटोकॉल का पालन करने का फैसला किया है और वह इस मैच के लिए श्रीलंका जाएगी। सूत्रों के अनुसार, भारत इस मैच के लिए अभ्यास करेगा और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेगा। टॉस के दौरान सूर्यकुमार यादव मैदान पर मौजूद रहेंगे और टीम इस बात का इंतजार करेगी कि मैच रेफरी मुक़ाबले को रद्द करें। आईसीसी से बात करेगा बीसीसीआई पाकिस्तान के फैसले को लेकर बीसीसीआई के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने कहा, इस बारे में आईसीसी का बड़ा बयान आया है। उन्होंने खेल भावना को लेकर बात की है और हम इस संबंध में आईसीसी से पूरी तरह सहमत हैं। बीसीसीआई इस बारे में तब तक कोई टिप्पणी नहीं करेगा जब तक कि हम आईसीसी से बात नहीं कर लेते हैं। आईसीसी पाकिस्तान की हरकत से नाबुश पाकिस्तान ने भले ही फैसला ले लिया है, लेकिन आईसीसी उसकी इस हरकत से खुश नहीं है। आईसीसी ने पाकिस्तान के रवैये पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि उसे अब तक पीसीबी की ओर से इस बारे में आधिकारिक तौर पर सूचित नहीं किया गया है।

# फॉर्म की दौड़ में आगे निकले ईशान सैमसन के लिए बढ़ी विश्व कप की चुनौती

**नई दिल्ली।** न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज में शानदार फॉर्म के दम पर ईशान किशन ने संजु सैमसन पर बढ़त बना ली है, जिससे विश्व कप प्लेइंग-11 की दौड़ और रोचक हो गई है। वहीं, खराब प्रदर्शन से संजु की चुनौती बढ़ी है और तिलक वर्मा की वापसी उनके लिए मुसीबत बन सकती है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेली गई पांच मैचों की टी20 सीरीज सिर्फ 4-1 की जीत पर नहीं थी,

भारत vs न्यूजीलैंड टी20 सीरीज			
04	पारियां	05	
215	रन	46	
231.2	स्ट्राइक रेट	135.30	
1/1	50/100	0	

बल्कि यह उन चयन बहरसों को भी तेज कर गई जो टी20 विश्व कप से ठीक पहले भारतीय टीम प्रबंधन के सामने खड़ी हैं। इस सीरीज में दो नाम सबसे ज्यादा चर्चा में रहे वो ईशान किशन और संजु सैमसन रहे। इस सीरीज में दोनों की वापसी एक-दूसरे से बिल्कुल उलट रही। मौके को भुनाने में कामयाब हुए ईशान सात फरवरी से भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में शुरू हो रहे टी20 विश्व कप के लिए भारतीय टीम का एलान हो चुका है। ईशान किशन भी 15 सप्टेंबीय टीम का हिस्सा हैं। इससे पहले न्यूजीलैंड के खिलाफ खेली गई पांच टी20 मैचों की सीरीज में ईशान का बल्ला जमकर गर्जा। चार मुक़ाबलों में ईशान ने 231.2 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए 215 रन बनाए। ईशान का प्रभाव सिर्फ रन बनाने तक सीमित नहीं था। उनकी बल्लेबाजी ने भारत के मिडिल ऑर्डर से

दबाव पूरी तरह हटा दिया। शीर्ष क्रम में आक्रमक शुरुआत, फिर नंबर-तीन पर आकर रफ्तार बनाए रखना यह वही रोल है जिसे मौजूदा भारतीय टी20 टीम सबसे ज्यादा अहमियत देती है। तिरुवनंतपुरम में लगाया गया 43 गेंदों का शतक इस बात का सबूत था कि ईशान सिर्फ हिट्टर नहीं, बल्कि मैच की स्थिति पढ़ने वाले बल्लेबाज भी बन चुके हैं। स्पिन के खिलाफ गिबर बदलना, तेज गेंदबाजों की गति का इस्तेमाल करना और 97 पर रकने की बजाय तुरंत बड़ा शॉट खेलना ये सब चयनकर्ताओं के लिए साफ संदेश था। संजु ने किया निराश संजु सैमसन के लिए यह सीरीज निराशाजनक रही। लंबे समय बाद उन्हें बतौर ओपनर लगातार मौके मिले, लेकिन उनका प्रदर्शन टीम प्रबंधन के भरपूर पर खरा नहीं उतर सका। पांच पारियों में वह सिर्फ 46 रन ही बना सके। संजु की समस्या सिर्फ रन न बनाना नहीं थी, बल्कि उनकी आउट होने की शैली भी चिंता का विषय रही। गेंद को जल्दी पढ़ने में पेशानी उनके लिए मुसीबत साबित हुई। तिरुवनंतपुरम में घरेलू मैदान पर उनसे बड़ी पारी की उम्मीद थी, लेकिन वही मैच उनकी मुश्किलों का प्रतीक बन गया। दबाव में खेलते हुए वह न तो लय में दिखे और न ही आत्मविश्वास में। चयन समीकरण और विश्व कप की तस्वीर विश्व कप से ठीक पहले फॉर्म सबसे बड़ा फेक्टर होता है, और फिलहाल इस कसौटी पर ईशान किशन संजु सैमसन से काफी आगे हैं। भारतीय टीम प्रबंधन आक्रमक शीर्ष क्रम के साथ आगे बढ़ना चाहता है, जहां हर ओवर में रन निकलें। इसी बीच तिलक वर्मा का नाम इस बारे में जुड़ गया है। फिलहाल, तिलक चोट से उबर रहे हैं। एशिया कप फाइनल जैसे बड़े मैच में वह मैच-विपर साबित हो चुके हैं। उम्मीद है कि विश्व कप की प्लेइंग 11 में उन्हें शामिल किया जा सकता है। टी20 विश्व कप के लिए भारत की संभावित प्लेइंग 11 अभिषेक शर्मा, संजु सैमसन/ईशान किशन (विकेटकीपर), तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), रिंकू सिंह, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह/हर्षित राणा, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह।



लखनऊ, (संवाददाता)। जशन रियल्टी ने लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की, जिसमें कंपनी के नेतृत्व ने आने वाले वर्षों के लिए अपनी महत्वाकांक्षी विकास योजना साझा की। मीडिया को संबोधित करते हुए राहुल अग्रवाल, प्रबंध निदेशक, जशन रियल्टी, ने बताया कि कंपनी आगामी तीन वर्षों में रियल एस्टेट विकास क्षेत्र में लगभग 3,200 करोड़ का निवेश करने जा रही है। प्रेस वार्ता के दौरान श्री अग्रवाल ने कहा कि जशन रियल्टी की विस्तार रणनीति उच्च गुणवत्ता वाले आवासीय और मिक्सड-यूज प्रोजेक्ट्स पर केंद्रित होगी, जो लखनऊ जैसे टिक्कर-प शहरों में बढ़ती मांग के अनुरूप हैं। उन्होंने शहर के तेजी से विकसित होते इन्फ्रास्ट्रक्चर, बेहतर कनेक्टिविटी और बढ़ते निवेशकों के विश्वास को इस बड़े निवेश निर्णय के प्रमुख कारण बताया। राहुल अग्रवाल ने यह भी स्पष्ट किया कि परियोजनाओं को तेज डिलीवरी कंपनी की सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। उन्होंने कहा, समय से पहले और तेज डिलीवरी अब केवल एक अतिरिक्त सुविधा नहीं, बल्कि हमारी प्रतिबद्धता है। जशन रियल्टी में हम अपनी प्रक्रियाओं को सुदृढ़ कर रहे हैं, निष्पादन टीमों को मजबूत बना रहे हैं और उन्नत निर्माण योजना को अपनाकर यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि हमारे प्रोजेक्ट्स तब तक संपन्न हो सकें जब तक कि हमारे कर्मियों को सुरक्षित रख सकें। कंपनी ने यह भी बताया कि आने वाले सभी प्रोजेक्ट्स में ग्राहक-केंद्रित डिजाइन, निवासीय अनुपालन और पारदर्शी निष्पादन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। जशन रियल्टी का लक्ष्य निर्माण गुणवत्ता, सुरक्षा और सतत विकास मानकों से समझौता किए बिना

# बांग्लादेश की पूर्व PM शेख हसीना को 10 साल की जेल भ्रष्टाचार से जुड़े दो मामलों में मिली सजा

# इस्राइल ने संघर्षविराम के तहत राफाह बॉर्डर को आंशिक रूप से खोला

**ढाका।** बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना को ढाका की स्पेशल जज कोर्ट-4 के जज रबीउल आलम ने भ्रष्टाचार से जुड़े दो मामलों में 10 जेल की सजा सुनाई है। इसके साथ कोर्ट ने उनके परिवार के सदस्यों को भी सजा सुनाई है। बता दें कि, शेख हसीना पर जमीन आवंटन में नियमों के उल्लंघन का आरोप है। बांग्लादेश की एक अदालत ने देश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को भ्रष्टाचार से जुड़े दो अलग-अलग मामलों में कुल 10 साल की जेल की सजा सुनाई है। ये मामले सरकार की एक आवासीय योजना में जमीन के आवंटन में गड़बड़ी से जुड़े हैं। ढाका की स्पेशल जज कोर्ट-चार के जज रबीउल आलम ने सोमवार को यह



शेख हसीना को 10 साल की जेल की सजा सुनाई है।

फैसला सुनाया। अदालत ने दोनों मामलों में शेख हसीना को पांच-पांच पांच साल की जेल की सजा सुनाई है। यह परिणाम राजधानी विकास प्राधिकरण (राजधानी उन्नयन कर्तृपक्खा) यानी राजुक के तहत आती है। परिवार के सदस्यों को भी सजा इन मामलों में शेख हसीना के साथ उनके परिवार के कई सदस्यों को भी दोषी ठहराया गया है। इसमें तुलिन सिद्दीकी को कुल चार साल की जेल, रदवान मुजीब सिद्दीकी और अजमीना सिद्दीकी को सात-सात साल की जेल की सजा मिली है। वहीं राजुक के सदस्य मोहम्मद खुर्शीद आलम, जिन्होंने अदालत में आत्मसमर्पण किया था, को दो साल की सजा मिली है। सभी आरोपियों ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए नियमों को तोड़ा और जमीन आवंटन की प्रक्रिया में हेरफेर किया। शेख हसीना को दोषी ठहराया गया है। इसमें तुलिन सिद्दीकी को कुल चार साल की जेल, रदवान मुजीब सिद्दीकी और अजमीना सिद्दीकी को सात-सात साल की जेल की सजा मिली है। वहीं राजुक के सदस्य मोहम्मद खुर्शीद आलम, जिन्होंने अदालत में आत्मसमर्पण किया था, को दो साल की सजा मिली है। सभी

की अनुमति दी जा रही है। मई पिछले साल के बाद यह पहला मौका है जब राफाह बॉर्डर को आंशिक रूप से खोला गया है। 'संघर्षविराम समझौते के तहत लिया गया फैसला' इस्राइल की सैन्य एजेंसी सीओजीएटी के अनुसार, यह फैसला संघर्षविराम समझौते के तहत लिया गया है। अधिकारियों ने बताया कि सोमवार से कुछ लोग इस रास्ते से आना-जाना शुरू कर सकते हैं। इसके लिए एक नई जांच (स्क्रीनिंग) सुविधा भी तैयार की गई है, जहां से गुजरने वाले लोगों की जांच होगी। 'गाजा छोड़ने वाले फलस्तीनी लौटना चाहते हैं' गाजा के सरकारी मीडिया कार्यालय ने कहा कि युद्ध के दौरान विश्वस्थित हुए हजारों फलस्तीनी इस फैसले का इंतजार कर रहे थे। मीडिया कार्यालय के प्रमुख इस्माइल अल-अवशाफि कहते हैं। इस खोज से पहले लोग मानते थे कि ग्लोबल वार्मिंग सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड से होती है। भारत से क्या है तालुक रामनाथन का जन्म मुद्रै में हुआ

# जोहरान ममदानी का न्यूयॉर्क में विरोध एपस्टीन विवाद से जुड़ा है मां मीरा नायर का नाम

**नई दिल्ली।** एपस्टीन से जुड़े नए दस्तावेज सामने आने के बाद न्यूयॉर्क सिटी के मेयर जोहरान ममदानी को ग्रेसी मैशन के बाहर विरोध झेलना पड़ा। दस्तावेजों में उनकी मां, फिल्ममेकर मीरा नायर का नाम 2009 की एक ईमेल में दर्ज है। प्रदर्शनकारियों ने समर्थन के बावजूद धोखा देने का आरोप लगाया। न्यूयॉर्क सिटी के मेयर जोहरान ममदानी को ग्रेसी मैशन के बाहर कुछ लोगों के विरोध और नारेबाजी का सामना करना पड़ा। यह घटना अमेरिकी न्याय विभाग द्वारा जेफ्री एपस्टीन से जुड़े नए दस्तावेज सार्वजनिक किए जाने के बाद सामने आई, जिनमें उनकी मां और महशूर फिल्ममेकर मीरा नायर का नाम एक ईमेल में दर्ज है। मेयर के आधिकारिक आवास ग्रेस मैशन के बाहर जुटे लोगों ने आरोप लगाया कि उन्होंने ममदानी का समर्थन किया था, लेकिन अब उन्हें

धोखा महसूस हो रहा है। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि हमने आपके लिए वोट किया, आपके लिए आवाज उठाई लेकिन आपने हमसे झूठ बोला। क्या है मामला? यह विवाद 21 अक्टूबर 2009 की एक ईमेल से जुड़ा है, जो अमेरिकी पब्लिसिस्ट पेगी सीगल द्वारा भेजी गई थी। ईमेल में दोषी यौन तस्कर थिसलेन मैक्सवेल के टाउनहाउस में आयोजित एक फिल्म स्क्रीनिंग के बाद हुए अपट्टर पार्टी का जिक्र है। ईमेल के मुताबिक, उस कार्यक्रम में बिल क्लिंटन, जेफ बेजोस, जीन पिगोर्जी और निदेशक मीरा नायर सहित कई हाई-प्रोफाइल लोग मौजूद थे। ईमेल में फिल्म का नाम नहीं दिया गया, लेकिन संदर्भ 2009 में रिलीज मीरा नायर की फिल्म अमेरिका से जोड़ा जा रहा है, जिसमें हिलेरी स्वीक और रिचर्ड गेरे ने अभिनय किया था। एपस्टीन फाइल का नया खुलासा बीते

शुरूवार को अमेरिकी न्याय विभाग ने एपस्टीन से जुड़े रिकॉर्ड्स का एक बड़ा नया सेट सार्वजनिक किया। यह रिलीज एपस्टीन फाइलस पारदर्शिता अधिनियम के तहत हुई, जिस पर 19 नवंबर 2025 को राष्ट्रपति ट्रंप ने हस्ताक्षर किए थे। नए दस्तावेजों में 30 लाख से अधिक पेज, 2,000 से ज्यादा वीडियो और करीब 1.8 लाख तस्वीरें शामिल हैं। ये रिकॉर्ड्स फ्लोरिडा और न्यूयॉर्क के मामलों, मैक्सवेल के खिलाफ केस, एपस्टीन की मौत की जांच, एफबीआई और इंस्पेक्टर जनरल की जांचों सहित कई स्रोतों से जुटाए गए हैं। ममदानी का राजनीतिक सफर 34 वर्षीय जोहरान ममदानी ने 1 जनवरी को न्यूयॉर्क सिटी के मेयर का पद संभाला। उन्होंने चुनाव में पूर्व गवर्नर एंड्रयू कुओमो और रिपब्लिकन उम्मीदवार कर्टिस स्लिवो को हराया। ये शहर के सबसे युवा और पहले मुस्लिम मेयर हैं। ममदानी ने एरिक एडम्स का स्थान लिया, जिन्होंने सितंबर में पुनर्निर्वाचन की दौड़ से नाम वापस ले लिया था, हालांकि वे बैलेट पर बने रहे।

बदल दिया है। इन क्षेत्र में हासिल की है बड़ी उपलब्धि 82 साल के रामनाथन ने 1975 में नासा में काम करते हुए एक बड़ी खोज की थी। रामनाथन ने रॉयल स्वीडिश एकेडमी के वैज्ञानिक वीरभद्रन रामनाथन को 2026 का प्रतिष्ठित क्रैफोर्ड पुरस्कार मिला है। इसे जियोसाइसेज का नोबेल माना जाता है। उन्होंने क्लोरोफ्लोरोकार्बन (उत्कृष्ट) और प्रदूषण के जलवायु पर असर को लेकर महत्वपूर्ण खोज की है। उनकी रिसर्च ने ग्लोबल वार्मिंग को समझने और पर्यावरण बचाने की अंतरराष्ट्रीय संधियों में बड़ी भूमिका निभाई है। रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइसेज ने भारतीय मूल के जलवायु वैज्ञानिक वीरभद्रन रामनाथन को 2026 के क्रैफोर्ड पुरस्कार के लिए चुना है। इस सम्मान को जियोसाइसेज का नोबेल भी कहा जाता है। रामनाथन को यह पुरस्कार प्रदूषण फैलाने वाले तत्वों और वायुमंडल के 'ब्राउन क्लाउड्स' पर उनके दशकों पुराने शोध के लिए मिला है। उनके काम ने ग्लोबल वार्मिंग को समझने का नजरिया



जोहरान ममदानी का न्यूयॉर्क में विरोध एपस्टीन विवाद से जुड़ा है मां मीरा नायर का नाम



वीरभद्रन रामनाथन को 2026 का प्रतिष्ठित क्रैफोर्ड पुरस्कार मिला है।

# पार्टी में नहीं गया, कुछ भी गलत नहीं किया, एपस्टीन फाइल में नाम आने पर मस्क ने तोड़ी चुप्पी

**वॉशिंगटन।** अमेरिकी न्याय विभाग ने 30 जनवरी को एपस्टीन फाइल से जुड़े और डॉक्यूमेंट्स जारी किए, जिसमें 30 लाख से अधिक पन्ने, 2000 से ज्यादा वीडियो और करीब 180,000 तस्वीरें शामिल हैं। जारी किए दस्तावेजों कई प्रभावशाली लोगों के नाम सामने आए हैं, जिसमें से एक फाइल में एलन मस्क का नाम भी शामिल है, जिस पर अब उन्होंने चुप्पी तोड़ी है। 30 लाख से अधिक पन्ने, 2000 से ज्यादा वीडियो और करीब 180,000 फोटो के साथ जारी होने वाली एपस्टीन फाइल की खेप ने एक बार फिर सुर्खियां बटोरी है। यौन अपराधी जेफरी एपस्टीन के साथ अमेरिका के कई दिग्गजों के संबंध उजागर हुए हैं। जिसमें एलन मस्क का नाम भी शामिल है। जिस पर टेक्सा के मालिक और टेक इंडस्ट्री के सबसे दिग्गज अरबपति ने जेफरी एपस्टीन से किसी भी तरह के रिश्ते से साफ इनकार किया है। एलन मस्क ने तोड़ी चुप्पी, अपना नाम आने की सफाई एलन मस्क ने बहुचर्चित एपस्टीन फाइल में नाम आने के बाद अपनी सफाई दी है। उन्होंने कहा कि वो कभी जेफरी एपस्टीन की पार्टियों में नहीं गए और ना उनका कोई संबंध है। सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट के जरिए मस्क ने चुप्पी तोड़ते हुए अपनी बात रखी। सोमवार को किए अपने पोस्ट में मस्क ने कहा कि वह कभी भी एपस्टीन के प्रहवेट द्वीप पर नहीं गए, न ही उनके लॉलित्ता एक्सप्रेस विमान में सफर किया और न ही उनकी पार्टियों में शामिल हुए।

अपने पोस्ट में मस्क ने क्या लिखा? अपने एक्स पोस्ट में एलन मस्क ने कहा, 'एपस्टीन फाइलों की पूरी तरह सार्वजनिक करने और बच्चों का शोषण करने वालों पर मुकदमा चलाने के लिए मुझे ज्यादा संघर्ष किसी ने नहीं किया, यह जानते हुए भी कि मुख्यधारा का मीडिया, धुर-वामपंथी प्रचारक और जो वास्तव में दोषी हैं, वे कुछ भी स्वीकार नहीं करेंगे, सब कुछ नकार देंगे, मुझ पर ही आरोप लगाएंगे।' 'ना कभी पार्टियों में गया और ना कभी उस आईलैंड पर कदम रखा' मस्क ने आगे कहा कि, 'मुझे पता था कि मुझे लगातार बदनाम किया जाएगा, जबकि मैंने कभी उसकी (जेफरी एपस्टीन) पार्टियों में शिरकत नहीं की, न ही उसके 'लोलित्ता एक्सप्रेस' विमान में सफर किया, न ही उसके उस 'घिनौने' द्वीप पर कदम रखा और न ही कोई गलत काम किया। फिर भी मुझे पर लगे उन आरोपों का असहनीय दृष्टि सहना सार्थक था, जो मेरे व्यक्तित्व के बिल्कुल विपरीत थे। ताकतवर लोगों को उनकी रक्षा करनी चाहिए, जो अपनी रक्षा नहीं कर सकते, विशेषकर कमजोर बच्चों की। बच्चों की रक्षा करने और उन्हें खुशहाल जीवन जीने का मौका देने के लिए मैं भविष्य में किसी भी तरह का दंड सहने को तैयार हूँ।' एपस्टीन फाइल में मस्क को लेकर क्या दावा? बता दें कि 30 जनवरी को जारी किए गए डॉक्यूमेंट्स में कई बार मस्क का नाम आया है। खासकर 2012 और 2013 के ईमेल अदला-बदली में, जिसमें उन्होंने एपस्टीन के बदनाम करे बिचियन आईलैंड कंपाउंड में जाने के बारे में बात की थी। हालांकि यह साफ नहीं है हुआ कि मस्क का आईलैंड पर जाना हुआ था या नहीं।

# ईरान ने यूरोपीय संघ के राजदूतों को किया तलब

# रिवोल्यूशनरी गार्ड को आतंकी घोषित करने पर जताया विरोध

**तेहरान।** ईरान ने यूरोपीय संघ के राजदूतों को बुलाकर रिवोल्यूशनरी गार्ड को आतंकी घोषित करने का विरोध किया है। यह तनाव ईरान में प्रदर्शनों पर हुई हिंसक कार्रवाई के बाद बढ़ा है। अमेरिका ने क्षेत्र में युद्धपोत तैनात किए हैं, जबकि ईरान ने जवाबी कार्रवाई और सैन्य अभ्यास की चेतावनी दी है। ईरान और यूरोपीय संघ (ईयू) के बीच कूटनीतिक तनाव बढ़ गया है। एपी की रिपोर्ट के मुताबिक, ईरान ने तेहरान में मौजूद यूरोपीय संघ के राजदूतों को तलब किया है। ईरान ने यह कदम यूरोपीय संघ के उस फैसले के विरोध में उठाया है, जिसमें उसने ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड को आतंकी घोषित करने की सूची में शामिल कर दिया है। ईरान के विदेश मंत्रालय ने ईयू के इन फैसले पर खतरा बरकरार यह तनाव ऐसे समय में बढ़ा है जब ईरान पर अमेरिकी सैन्य हमले का खतरा मंडरा रहा है। हालांकि, अभी यह साफ नहीं है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बल प्रयोग करेंगे या नहीं। इस बीच, क्षेत्र के अन्य देश युद्ध रोकने के लिए कूटनीति का सहारा ले रहे हैं। क्या है मामला? यूरोपीय संघ ने पिछले हफ्ते रिवोल्यूशनरी गार्ड को आतंकी सूची में डाला था। इसका मुख्य कारण जनवरी में हुए देशव्यापी विरोध प्रदर्शनों को बेरहमी से कुचलना बताया गया। इन प्रदर्शनों में हजारों लोग मारे गए और हजारों को हिरासत में लिया गया। अमेरिका और कनाडा पहले ही इस संगठन को आतंकी घोषित कर चुके हैं। हालांकि यह फैसला काफी हद तक प्रतीकात्मक है, लेकिन इससे ईरान पर आर्थिक दबाव बढ़ेगा, क्योंकि वहां की अर्थव्यवस्था में इस गार्ड का बहुत बड़ा प्रभाव है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता क्या कहा? ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगई ने बताया कि राजदूतों को बुलाने की प्रक्रिया रविवार से शुरू हो गई थी। उन्होंने कहा कि ईरान इस अवैध और गलत कदम का जवाब देने के लिए कई विकल्पों पर विचार कर रहा है। जल्द ही जवाबी कार्रवाई के बारे में फैसला लिया जाएगा। वहीं, ईरान की संसद के स्पीकर ने 2019 के एक कानून का हवाला देते हुए कहा, अब ईरान भी यूरोपीय संघ की सभी

सेनाओं को आतंकी घोषित करेगा। अमेरिकी ने ही चेतावनी रिवोल्यूशनरी गार्ड ईरान की 1979 को इस्लामिक क्रांति से एक ऐसी ताकत के रूप में उभरा था, जिसका मकसद शिया मौलवी-पर्यवेक्षित सरकार की रक्षा करना था। बाद में इसे संविधान में शामिल किया गया। आज यह ईरान की नियमित सेना के बराबर शक्तिशाली है। इस बीच ईरान ने होर्मुज जलडमरूमध्य में सैन्य अभ्यास भी शुरू किया है। यह समुद्री रास्ता दुनिया के तेल व्यापार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अमेरिकी ने ईरान को कड़ी चेतावनी दी है कि वह व्यापारिक जहाजों या अमेरिकी युद्धपोतों के काम में बाधा न डाले।

# 39 वर्षीय महिला फर्नांडीज राष्ट्रपति की दौड़ में आगे मतगणना में मिली बढ़त

कोस्टा रिका के राष्ट्रपति चुनाव के शुरूआती परिणाम आने लगे हैं। इसके अनुसार दक्षिणपंथी, कानून-व्यवस्था समर्थक उम्मीदवार लौरा फर्नांडीज ने मजबूत बढ़त बना ली है। आइए जानते हैं कैसे कितने फीसदी वोट मिले। कोस्टा रिका के राष्ट्रपति चुनाव में दक्षिणपंथी कानून-व्यवस्था समर्थक उम्मीदवार लौरा फर्नांडीज ने शुरूआती दौर में मजबूत बढ़त हासिल कर ली है। अल जजीरा की रिपोर्ट के अनुसार, शुरूआत परिणामों के मुताबिक, प्रारंभिक मतगणना के आधार पर रविवार देर रात तक 31 प्रतिशत मतदान केंद्रों से प्राप्त मतों की गिनती से पता चला कि सत्तारूढ़ सॉवरेन पीपुल्स पार्टी (पीपीएसओ) की फर्नांडीज ने 53.01 प्रतिशत वोट हासिल किए हैं, जिससे वह शुरूआती दौड़ में आगे चल रही हैं। पूर्व प्रथम महिला तीसरे नंबर पर रिपोर्ट के अनुसार, दूसरे स्थान पर मध्य-वामपंथी नेशनल लिबरेशन पार्टी के अल्बार्तो रामोस 30.05 प्रतिशत वोटों के साथ रहे। वहीं, पूर्व प्रथम महिला क्लाउडिया डोब्लेस 3.9 प्रतिशत वोटों के साथ तीसरे स्थान पर रही। इन आंकड़ों के साथ, फर्नांडीज को अब स्पष्ट जीत हासिल करने और 5 अप्रैल को होने वाले दूसरे दौर के चुनाव से बचने के लिए कम से कम 40 प्रतिशत वोटों की आवश्यकता है। उनकी लोकप्रियता में यह उछाल ऐसे समय आया है जब 39 वर्षीय राजनेता मौजूद राष्ट्रपति रेडिगो चावेस के चुने हुए उत्तराधिकारी के रूप में चुनाव प्रचार कर रही हैं। उनके कड़े सुस्था एजेंडे को आगे बढ़ाने का वादा कर रही हैं। हाल के वर्षों में परंपरागत रूप से शांतिपूर्ण रहे मध्य अमेरिकी देश में अपराध में तेजी से वृद्धि हुई है, जिससे सार्वजनिक सुरक्षा कई मतदाताओं के लिए एक निर्णायक मुद्दा बन गई है। अल जजीरा के अनुसार, जहां कुछ लोग हिंसा पर अंकुश लगाने में विफल रहने के लिए चावेज प्रशासन को दोषी ठहराते हैं। वहीं अन्य लोग उनके टकरावपूर्ण दृष्टिकोण को व्यवस्था बहाल करने का सबसे मजबूत विकल्प मानते हैं। 57 सीटों वाली राष्ट्रीय सभा के सदस्यों का भी चुनाव फर्नांडीज ने खुद को चावेस के साथ घनिष्ठ रूप से जोड़ लिया है, क्योंकि उन्होंने पहले उनकी राष्ट्रीय योजना और आर्थिक नीति मंत्री के रूप में और बाद में राष्ट्रपति पद की मंत्री के रूप में कार्य किया है। राष्ट्रपति चुनाव के साथ-साथ, कोस्टा रिका के लोगों ने 57 सीटों वाली राष्ट्रीय सभा के सदस्यों का भी चुनाव किया। अल जजीरा की रिपोर्ट के अनुसार, चावेज की पार्टी को बढ़त मिलने की उम्मीद है, हालांकि हो सकता है कि उसे चावेज और फर्नांडीज द्वारा अंधविश्वास बढ़ाने में मिले, जिससे उनके गुट को अलग-अलग रूप से साथ-साथ सर्वोच्च पाठ्यालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करने का अधिकार मिल जाएगा। उनमें 20 उम्मीदवारों ने चुनाव में भाग लिया, लेकिन न्यायिक और आंशिक परिणामों से पता चला कि फर्नांडीज और रामोस के अलावा कोई भी उम्मीदवार 5 प्रतिशत का आंकड़ा पार नहीं कर सका।

# बलूचिस्तान में हिंसा तेज महिला फिदायीन हमले में पाकिस्तानी सेना-पुलिस के 200+ जवान हताहत

**इस्लामाबाद।** बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने दावा किया है कि उसने 200 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों, पुलिस और फ्रंटियर कोर के कर्मियों को मारा गया है। बीएलए के अनुसार, उसके इस ऑपरेशन में महिला फिदायीनों ने अहम भूमिका निभाई है। हालांकि पाकिस्तान ने इन आंकड़ों से अलग आंकड़े कबूल हैं। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में अलगाववादी संगठन बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी (बीएलए) ने दावा किया है कि उसका एक बड़ा सैन्य अभियान 'ऑपरेशन हीरोफ फेज-कर्म 40 घंटे से ज्यादा समय तक चला। इस दौरान कई जिलों में हमले किए गए और पाकिस्तानी सुरक्षा बलों को भारी नुकसान पहुंचाया गया। बीएलए का क्या है दावा? बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के प्रवक्ता जौद बलोच के मुताबिक, इस ऑपरेशन में पाकिस्तानी सेना, पुलिस और फ्रंटियर कोर के 200 से ज्यादा जवान मारे गए हैं। जबकि 17 लोगों को फकड़ा गया है। उन्होंने आगे बताया कि बीएलए की तरफ से करान, मस्तुंग, तुंग और पसनी जैसे इलाकों में अभियान पूरा किया गया, इसके साथ ही क्वेटा और नोश्की के कुछ हिस्सों में पाकिस्तानी सेना को पीछे धकेला गया है। हालांकि, इन दावों की पुष्टि नहीं हो सकी है। इंडअ के हमले पर सरकार और सेना की सफाई बलूचिस्तान के मुख्यमंत्री सरफराज बुखारी ने कहा कि बलोचों के हमलों में 17 सुरक्षाकर्मी और 31 आम नागरिक मारे गए हैं। वहीं पाकिस्तानी सेना के अनुसार, शुरूवार को 41 और शनिवार को 92 अज्ञात मारे गए हैं। महिला आत्मघाती हमलावरों की भूमिका इस अभियान की सबसे चौकाने वाली बात यह रही कि महिला फिदायीन (आत्मघाती हमलावर) भी शामिल थीं। आसिफा मेंगल ने नोश्की में इंटर-सर्विसेज इंस्टिट्यूट (आईएसआई) मुख्यालय को निशाना बनाकर कार बम से हमला किया।



महिला आत्मघाती हमलावरों की भूमिका इस अभियान की सबसे चौकाने वाली बात यह रही कि महिला फिदायीन (आत्मघाती हमलावर) भी शामिल थीं।